नई दिल्ली ■ शुक्रवार 09 जनवरी 2026 ■ मूल्य 5.00 ■ वर्ष 13 ■ अंक 282 ■ पृष्ठ 08

JBT

जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 प्रवासी भारतीय और 2047 का संकल्प | 07 पीवी सिंधू ने जीत के साथ मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में | एकता कपूर के शो में लीड रोल अदा करेगी ऐश्वर्या शर्मा 08

आई-पैक निदेशक के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने की छापेमारी

छापे के दौरान सबूत अपने साथ ले गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कथित कोयला तस्करी से जुड़े धनशोधन मामले में आई-पैक के निदेशक प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास में उसकी छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जबरन इमारत में दाखिल हो गईं और दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित 'महत्वपूर्ण' सबूत अपने साथ ले गईं।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी साल्ट लेक स्थित आई-पैक कार्यालय भी पहुंच गईं और उन्होंने, उनके सहयोगियों और राज्य पुलिस ने 'जबरन मौके से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हटा दिए'। ईडी ने बताया कि उसका धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2020 में अनूप मांझी उर्फ 'लाला' के नेतृत्व वाले कोयला तस्करी गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। उसने बताया कि इसके तहत पश्चिम बंगाल के छह और दिल्ली के चार सहित कुल 10 परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई का आरोप है कि इस गिरोह ने ईस्टर्न कोल्डफिल्ड की खदानों और पश्चिम बर्धमान जिले के कोयला क्षेत्रों से कोयले का अवैध रूप से खनन किया और उसकी तस्करी की।

संघीय एजेंसी के मुताबिक कोयला तस्करी से जुड़े एक हवाला कारोबारी ने राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पैक की पंजीकृत कंपनी इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपये के लेनदेन में सुविधा प्रदान की। ईडी ने आरोप लगाया कि आई-पैक भी हवाला के पैसों से जुड़े संगठनों में से एक है। उसके मुताबिक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ आने तक छापेमारी की कार्यवाही शांतिपूर्ण और पेशेवर तरीके से चल रही थी।'

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी आई-पैक के सह-संस्थापक और पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में दाखिल हो गईं और दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं। ईडी ने कहा कि ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त के कदम से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच और कार्यवाही में 'बाधा' उत्पन्न हुई।

बयान में कहा गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि तलाशी साक्ष्य-आधारित है और किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर नहीं की जाती। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है। ईडी ने कहा कि यह तलाशी किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं है, और यह धनशोधन के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। यह स्थापित कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही की जा रही है।

ईडी की जांच में 'दखल' करने वाली ममता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए: शुभेंदु

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोयला तस्करी गिरोह के धन शोधन मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के काम में कथित तौर पर हस्तक्षेप करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की बृहस्पतिवार को मांग की। ईडी की छापेमारी के दौरान पहले 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और बाद में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चुनाव सलाहकार के मुख्य कार्यालय में पहुंचीं बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति से जुड़े आंतरिक दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और संवेदनशील डिजिटल डेटा को जब्त करने का प्रयास कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दौरान उन स्थानों पर दिए गए बनर्जी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि एक वैध जांच प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने या संवैधानिक प्रक्रिया को कमजोर करने के प्रयास केवल संस्थानों और कानून के शासन में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं।

भारतीय एआई स्टार्टअप को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत पर दुनिया का विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मॉडल नैतिक, निष्पक्ष और पारदर्शी होने के साथ-साथ डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हों।

उन्होंने यह भी कहा कि स्टार्टअप को इस देश से वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम करना चाहिए और उल्लेख किया कि भारत वहनीय एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को विश्व स्तर पर बढ़ावा दे सकता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' से पहले, भारतीय एआई स्टार्टअप के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होने चाहिए और उन्हें स्थानीय और स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्यमी देश के भविष्य के सह-निर्माता हैं। अगले महीने आयोजित होने वाले 'एआई फॉर ऑल: ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज' शिखर सम्मेलन के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके 12 भारतीय एआई स्टार्टअप ने बैठक में भाग लिया तथा अपने विचारों और कार्य से अवगत कराया। बैठक के दौरान, मोदी ने समाज में परिवर्तन लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले महीने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट' शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एआई का लाभ उठाकर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सह-निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि देश में नवाचार और व्यापक कार्यान्वयन, दोनों की अपार क्षमता है। मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए जो 'मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' की भावना को प्रतिबिंबित करे। ये स्टार्टअप विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिनमें भारतीय भाषा फाउंडेशन मॉडल, बहुभाषी एलएलएम, 'स्पीच-टू-टेक्स्ट, टेक्स्ट-टू-ऑडियो और टेक्स्ट-टू-वीडियो' के अलावा ई-कॉमर्स, मार्केटिंग और व्यक्तिगत सामग्री निर्माण के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करके 3डी सामग्री तैयार करना शामिल हैं। इनमें इंजीनियरिंग सिमुलेशन और विभिन्न उद्योगों में डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए उन्नत विश्लेषण तथा स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा अनुसंधान आदि शामिल हैं।

संक्षिप्त खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया। जस्टिस वर्मा का कहना है कि जब 21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था तो ऐसी सूरत में जजेज इन्क्वारी एक्ट के तहत आगे जांच के लिए दोनों सदनों की संयुक्त कमेटी का गठन होना चाहिए था। ऐसे में लोकसभा स्पीकर की ओर से कमेटी का गठन होना गलत है।जस्टिस वर्मा की याचिका में कहा गया है कि जजेज इन्क्वायरी में साफ तौर पर उल्लेख है कि अगर किसी जज को हटाने का प्रस्ताव एक ही दिन में संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, तो तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं होगा, जब तक संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लेते।

मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

नयी दिल्ली। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को बृहस्पतिवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति गुप्ता इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पदस्थ हैं। वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र के 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर शुक्रवार को पद छोड़ने के बाद कार्यभार संभालेंगे। उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने पिछले महीने न्यायमूर्ति गुप्ता की पदोन्नति की सिफारिश की थी। उन्हें 12 अप्रैल, 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह आठ अक्टूबर, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

पर्यावरणविद माधव गाडगिल का पुणे में निधन, कई नेताओं ने जताया दुख

नई दिल्ली। प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गाडगिल का बुधवार देर रात महाराष्ट्र के पुणे स्थित आवास पर निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। उनके पुत्र सिद्धार्थ गाडगिल ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार शाम 4 बजे पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट पर किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई प्रमुख लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गडकरी ने कहा कि गाडगिल ने अपना पूरा जीवन पर्यावरणीय चेतना को जीवंत बनाए रखने और पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित किया। गाडगिल का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। उन्होंने जिस तरह से पर्यावरण और जैव विविधता के मुद्दों को जन चेतना से जोड़ा, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है।

ढाका ने भारत में वीजा सेवा निलंबित की

ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर दिल्ली सहित भारत में स्थित अपने प्रमुख मिशनों से वीजा सेवाएं निलंबित करने को कहा है। विदेश मामलों के सलाहकार एम.तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि बांग्लादेश ने अमेरिका द्वारा हाल में लागू की गई 'वीजा बॉन्ड' की आवश्यकता को भी रद्द करने की मांग की है।

हुसैन ने कहा कि मैंने भारत में स्थित अपने तीनों मिशनों को फिलहाल वीजा संबंधी खंड बंद रखने के लिए कहा है। यह सुरक्षा का मामला है।" सलाहकार की यह टिप्पणी तब आई जब कोलकाता स्थित बांग्लादेश के उप उच्चायोग ने रातोंरात वीजा सेवाओं को बंद कर दिया, जबकि दिल्ली और अगरतला में भी इसी तरह के कदम उठाए गए थे, जिनमें व्यापार और कार्य वीजा को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। बांग्लादेश के मुंबई और चेन्नई में भी राजनयिक मिशन हैं, जहां वीजा सेवाएं चालू रहीं। भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इससे पहले पांच अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा पर रोक लगा दी थी। जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश और भारत के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।

कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड के माध्यम से गांधी परिवार को दी रिश्वत : प्रह्लाद जोशी

बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से नेशनल हेराल्ड अखबार को करदाताओं का पैसा देकर नेहरू-गांधी परिवार को 'रिश्वत' दी।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जोशी ने यहां पत्रकारों से कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने देश के किसी भी स्थापित समाचार पत्र या पत्रिका की तुलना में नेशनल हेराल्ड अखबार को कहीं अधिक विज्ञापन राजस्व दिया है। यह अपने आप में एक घोटाला है। उन्होंने कहा कि इस अखबार के तथाकथित मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस घोटाले के सिलसिले में जमानत पर बाहर हैं। इसके बावजूद

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2023-24 में दो करोड़ रुपये और 2024-25 में एक करोड़ रुपये दिए। हमें नहीं पता कि उन्होंने इस साल कितना दिया।

उन्होंने दावा किया कि जमानत पर छूटे लोगों को पैसा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसका मतलब है कि घोटालों में फंसे जो लोग जमानत पर हैं, उनके लिए कर्नाटक सरकार इतनी बड़ी रकम चुका रही है। इसका मतलब है कि यह एक तरह से 'नकली गांधी परिवार' को रिश्वत देना है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है कि वीबी-जी-राम-जी योजना ग्रामीण रोजगार छीन लेगी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है।

वीबी-जी-राम-जी संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसलिए, यह कहना निराधार है कि इससे रोजगार छिन जाएगा। हम 120 दिनों का रोजगार देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में गारंटीशुदा नौकरियां छीने जाने के कांग्रेस के आरोप का कोई आधार नहीं है और दावा किया कि पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के रोजगार गारंटी कार्यक्रम में 'व्यापक भ्रष्टाचार' था। संसद के शीतकालीन सत्र में भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) विधेयक पारित किया गया था जिसने मनरेगा का स्थान लिया है।

कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट, फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित रहा

नई दिल्ली। उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है, जिसका सीधा असर रेल एवं हवाई यातायात पर पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण कई उड़ानें लेट हुईं और फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित रहा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण हवाई परिचालन बाधित हुआ।

एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने की वजह से सात उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू उड़ानें घंटों देरी से रवाना हुईं। कम दृश्यता के कारण पायलटों को टेक-ऑफ और लैंडिंग में परेशानी हुई। देश के विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचने वाली कई प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से चली। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडिगो की दिल्ली-अमृतसर फ्लाइट 6ई-5103 रद्द कर दी गई। स्पाइसजेट की दिल्ली-वाराणसी फ्लाइट एसG-8718 एवं दिल्ली-श्रीनगर फ्लाइट एसG-661 उड़ान नहीं भर सकीं। वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-अमृतसर फ्लाइट आईएक्स-1683 एवं एयर इंडिया की दिल्ली-गुवाहाटी फ्लाइट आईएक्स-1030 भी रद्द कर दी गईं, जबकि कुछ उड़ानें देरी से भी संचालित हुईं हैं। इंडिगो ने एक्स पर हवाई यात्रियों के लिए एक यात्रा परामर्श जारी किया है।

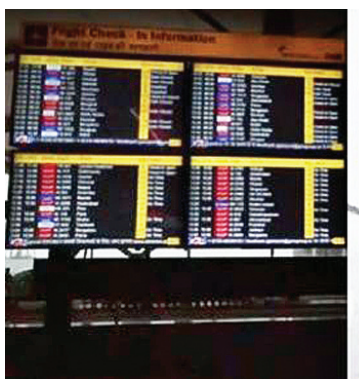

कंपनी ने कहा कि प्रयागराज में कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ सकता है। हम मौसम पर करीब से नज़र रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और आसानी से आपकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एयरलाइन ने कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप के ज़रिए अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें। कृपया निश्चिंत रहें कि हमारी टीमें हर कदम पर आपकी मदद करने और पूरा सपोर्ट देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि आसमान साफ़ होगा और हम जल्द ही अपने रेगुलर शेड्यूल पर वापस लौटेंगे। आपके धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद।

जम्मू कश्मीर के सीएम ने ई-पाठशाला का उद्घाटन किया

जम्मू। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को स्कूल शिक्षा विभाग की ई-पाठशाला पहल का उद्घाटन करते हुए कहा कि 'डिजिटल' मंच का उद्देश्य कक्षा शिक्षण का पूरक बनना है। केंद्र शासित प्रदेश में घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ई-पाठशाला चैनल डीटीएच चैनल 53 पर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने समग्र शिक्षा योजना के तहत नए छात्रावास भवनों और अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि यह पहल डिजिटल शिक्षण संसाधनों के विस्तार की दिशा में एक शुरुआत है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य प्रत्येक कक्षा के लिए एक समर्पित चैनल बनाना है। उन्होंने कहा कियह तो बस एक छोटा सा कदम है। हमारा इरादा यह होना चाहिए कि हर कक्षा का अपना चैनल हो। धीरे-धीरे हम इन चैनलों का विस्तार करेंगे और हर कक्षा के लिए एक अलग चैनल होगा।

लैंड फॉर जॉब मामला

लालू और अन्य के खिलाफ आरोप तय, फैसला आज

नई दिल्ली। लैंड फॉर जॉब मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर आज फैसला सुनाएगा। स्पेशल जज विशाल गोगने फैसला सुनाएंगे।

इससे पहले 19 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सभी आरोपितों से संबंधित वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में 103 आरोपित हैं जिसमें से पांच की मौत हो चुकी है। कोर्ट आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर दो बार 4 दिसंबर और 10 नवंबर, 2025 को फैसला टाल चुका है। कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की आरोपित राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने 19 दिसंबर को राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने 18 जुलाई, 2025 को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी, 2025 को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

ऑनलाइन गेमिंग ठगी गिरोह का पर्दाफाश पांच युवतियां समेत आठ आरोपी गिरफ्तार

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने ऑनलाइन गैमिंग एप/ऑनलाइन गैंबलिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 युवतियां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 18 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 155 प्रयोग शुदा फर्जी सिम, 50 पेमेन्ट क्यूआर कोड़, 45 हजार रुपये नकद, 2 कम्प्यूटर मॉनीटर, 4 वाई-फाई माडम, 10 पेज डाटाशीट व 10 कॉलिंग हेडफोन बरामद की है।

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से ऑनलाइन गैमिंग एप/ऑनलाइन गैंबलिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अभियुक्त गर्व पुत्र राजकुमार चौहान, अजय सिहं पुत्र रामेश्वर सिंह, सोनल उर्फ अनिरुद्ध पुत्र राजेंद्र व अभियुक्ता रुचि पुत्री अशोक, कोमल पुत्री सुनील सिंह, सुषमा पुत्री दिलवर रावत तनीषा पुत्री विशाल मित्तल, सानिया सिंह पुत्री कमल प्रताप को चौथी मंजिल, गौर सिटी सेन्टर निकट चार मूर्ति चौराहा से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिकेट, कसीनो, एविएटर, रूलेट और नंबरिंग गेम जैसे खेल खिलवाते थे। शुरुआत में ग्राहकों को छोटी-छोटी रकम जितवाकर उनका भरोसा और लालच बढ़ाया जाता था। जैसे ही ग्राहक अधिक धनराशि लगाने लगता, खेल का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर उसे लगातार हरवाया जाता और उसकी जमा पूंजी डुबो दी जाती थी।

यदि कोई ग्राहक जीतकर रकम निकालने की बात करता तो उसे तकनीकी बहानों से टाल दिया जाता या बड़ी राशि की शर्त लगाकर भुगतान रोका जाता था। ज्यादा दबाव बनाने पर ग्राहकों को ब्लॉक कर दिया जाता और पूरी रकम हड़प ली जाती थी।

गिरोह फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर सिम कार्ड खरीदता था। उन्हीं सिम कार्डों पर अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाए जाते थे। ग्राहकों से पैसे इन्हीं खातों और क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रांसफर कराए जाते थे। बरामद सिम कार्ड प्री-एक्टिवेटेड थे, जिन्हें अलग-अलग राज्यों के पते दिखाकर लिया गया था। पुलिस को इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित कई बैंकों के खातों की डिटेल मिली है, जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसों के लेनदेन में किया जाता था। वहीं एसीपी सेंट्रल नोएडा दीक्षा सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी सोनल उर्फ अनिरुद्ध ने पूछताछ में बताया कि वह कॉलिंग और डाटा मैनेजमेंट का काम देखता था। वह ऐसे लोगों का डाटा जुटाता था जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन गेम खेले हों या इस तरह के विज्ञापनों में रुचि दिखाई हो। इसके बाद कॉलिंग स्टाफ उन लोगों को फोन कर अधिक कमाई का लालच देता था। नए ग्राहकों को लुभाने के लिए बोनस और फ्री गेम की सुविधा भी दी जाती थी, जिसे निकाला नहीं जा सकता था। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपये के लेनदेन की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि ऑनलाइन गेमिंग या निवेश के नाम पर मिलने वाले लालच से बचें। किसी भी अनजान ऐप या लिंक पर पैसे लगाने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें।

पीने के पानी की आपूर्ति में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई लोग बीमार

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर में घरों में पीने के पानी की आपूर्ति में सीवर का गंदा पानी मिलने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। निवासियों का आरोप है कि तीन दिनों तक लगातार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया।

स्थानीय निवासी प्रमोद भाटी ने गुरुवार को बताया कि पिछले तीन दिनों से सेक्टर में पीने के पानी के साथ सीवर का पानी मिलकर आ रहा है और 25 से 30 लोग दूषित पानी का शिकार हुए हैं। इस संबंध में प्राधिकरण में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी ऐसी स्थिति में लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। डेल्टा निवासी विजय सिंह ने बताया कि पिछले तीन दिनों से सप्लाई का पानी बिल्कुल पीला और गंदा आ रहा है। उनके घर में भी बच्चे उल्टी और दस्त की समस्या से बीमार हुए हैं।

रुक्मणी सिंह भाटी ने भी पानी से बदबू आने और बच्चों के बीमार होने की बात कही। निवासियों के अनुसार, इस दूषित पानी के कारण कई लोगों को उल्टी, दस्त, सिरदर्द और बुखार जैसी दिक्कतें आई हैं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीनियर मैनेजर विनोद कुमार ने बताया कि आज प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने कई स्थानों पर गड्ढे खोदकर जांच की और पानी के नमूने भी लिए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पीने के पानी की लाइन में सीवर लाइन का पानी मिल गया है। उस पैच को ठीक कर दिया गया है। यह दिक्कत एक दो घरों में आई थी। अब फिलहाल पानी सभी घरों में ठीक आ रहा है।

भूखंड कब्जाने की शिकायत

ग्रेटर नोएडा। खेड़ा चौगानपुर गांव में प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में भूखंड पर कब्जा करने की कोशिश और अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया है। प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक राजीव कुमार ने सेक्टर ईकोटेक-3 कोतवाली में लिखित शिकायत दी कि खेड़ा चौगानपुर में खसरा संख्या-126 के एक भूखंड पर गांव के दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। इस संबंध में भूखंड मालिक सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से केपी-5 में भूखंड संख्या-33ए ग्राम चौगानपुर में खरीदा है, जिस पर दबंग प्रवृत्ति के लोग प्रदीप भाटी, कुलदीप भाटी और संजीव भाटी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस बात की सूचना उन्होंने प्राधिकरण को दी। प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर उक्त लोगों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

चिराग पासवान ने ग्रेटर नोएडा में इंडसफूड प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

ग्रेटर नोएडा । केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक खाद्य एवं पेय पदार्थ (एफएंडबी) सोर्सिंग प्रदर्शनी इंडसफूड 2026 कार्यक्रम भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का एक सशक्त मंच है।

पासवान ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो- इंडसफूड 2026 के 9वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में यह बात कही। इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इंडसफूड का 9वां संस्करण 8-10 जनवरी 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया है। प्रदर्शनी में 120 से अधिक देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें हजारों सत्यापित वैश्विक खरीदार और कई उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। इंडसफूड 2026 में वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए समर्पित मंच भी होंगे, जिनमें डीपी वर्ल्ड द्वारा आयोजित एक विशेष 'भारत मार्ट' सत्र शामिल है।

प्राधिकरण ने कराई सरकारी जमीन कब्जामुक्त

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के अतिक्रमण हटाओ टीम ने गुरूवार को 3 ग्राम के अधिसूचित क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों की भूमि को भू-माफिया के चंगुल से बचा लिया। प्राधिकरण के आला-अफसरों द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया। जो पुलिस बल देखकर भाग गए।

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा. लोकेश एम ने प्राधिकरण के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नोएडा के कार्यवाही करते हुए वर्क सर्किल-8 के कार्यक्षेत्र में अधिसूचित व अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर विभिन्न भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अतिक्रमणों के खिलाफ आज कार्यवाही की। शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्राधिकरण द्वारा यह विशेष कदम उठाया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा. लोकेश एम के निर्देश पर आज वर्क सर्किल-8 के द्वारा ग्राम भंगेल बेगमपुर के खसरा संख्या-58 से अतिक्रमण हटाया गया। यहां लगभग 2000 वर्ग मीटर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गयी।

वहीं ग्राम सुधियाना सेक्टर-143 के डूब क्षेत्र में नोएडा की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त लगभग 75000 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसके अलावा आज ग्राम सौरखा जाहिदाबाद के डूब क्षेत्र में नोएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गय जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6000 वर्ग मीटर है। वर्क सर्किल-8 के अधिकारियों ने बताया कि इस पूरी कार्रवाई में नोएडा प्राधिकरण के लगभग 70 छोटे-बड़े कर्मचारी, 5 जेसीबी मशीने, 2 डम्परों का प्रयोग करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।

उन्होंने बताया कि अतिक्रमण मुक्त भूमि की बाजारू कीमत करोड़ रुपये में है। उसका सही मूल्यांकन कराया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने लोगों से अपील की है कि नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

उप निरीक्षक ने दो लोगों के खिलाफ दर्ज कराया पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज कराया मुकदमा

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुध नगर जिले के थाना दादरी में तैनात उप निरीक्षक ने दो लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाने में मामला दर्ज करवाया है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। दादरी थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक मलूक सिंह रात को गस्त पर थे और उन्हें सूचना मिली कि कोट चैकी के पास राजमार्ग पर एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें दो लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और जब उक्त गाड़ी की जांच की गयी तो उसमें पशुओं का मांस रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि दोनों अलीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि शक होने पर उप निरीक्षक ने वहां प्राप्त मांस को जांच के लिए भेजा है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को आशंका है कि आरोपी गोकशी करके मीट को दिल्ली बेचने के लिए ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

स्कूल का मित्र बनकर साइबर अपराधी ने 6.64 लाख रुपए ठगे

नोएडा। थाना साइबर क्राइम में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अज्ञात साइबर अपराधी ने उससे संपर्क किया तथा कहा कि वह उसका पुराना मित्र बोल रहा है। उसने स्कूल के समय की जानकारी दी। पीड़ित को उसकी बात पर विश्वास हो गया। आरोपित ने उसे अपने जाल में फंसाकर कहा कि उसके एक रिश्तेदार की मेडिकल इमरजेंसी है। कुछ पैसा भेजना है।

बैंक के नियमों के अनुसार वह पूरा पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। पीड़ित के अनुसार आरोपित ने अपने जाल में फंसाकर उससे 6 लाख 64 हजार 237 रूपए की ठगी कर ली। अपर पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने गुरुवार को बताया कि नोएडा के सेक्टर-78 स्थित अंतरिक्ष गोल व्यू सोसाइटी में रहने वाले जयप्रकाश सैनी पुत्र मुंशी राम सैनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बीते 23 अक्टूबर को उनके पास अनिल सक्सेना नामक एक व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि वह उनके स्कूल के समय का दोस्त बोल रहा है। उन्हें शुरुआती दौर में कुछ शक हुआ, लेकिन उसने स्कूल के समय का निक नेम का जिक्र किया तो जिससे पीड़ित को विश्वास हो गया कि यह उनका पुराना स्कूली मित्र है।

पीड़ित के अनुसार आरोपी ने उनसे कहा कि उसके एक रिश्तेदार को मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ रहा है। बैंक की लिमिट की समस्या के कारण वह उसे पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। आरोपित ने उससे अपने रिश्तेदार के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट किया। पीड़ित के अनुसार वह उसकी बातों में आ गए तथा उन्होंने विभिन्न बार में बताए हुए अकाउंट में 6 लाख 64 हजार 237 रुपए ट्रांसफर कर दिया। पीड़ित के अनुसार बाद में उन्हें पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। अपर उपायुक्त ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है की रकम किन-किन खातों में गई है।

विभिन्न सड़क हादसों में तीन की मौत

नोएडा। नोएडा के विभिन्न जगहों पर हुए विभिन्न सड़क हादसों में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने गुरुवार को बताया कि थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 98 के पास सदरपुर कॉलोनी में रहने वाले अंकित चौहान (27) पुत्र रणवीर चौहान एक्सप्रेसवे पर पैदल सड़क पार कर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस द्वारा उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है।

थाना फेस-2 के प्रभारी निरीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि विनोद कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके पिता मुन्ना सिंह पुत्र शीशराम 7 जनवरी को सेक्टर-93 के पास नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे थे। तभी अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दिया। उन्हें उपचार के लिए एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर बुधवार की देर रात को उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से पुलिस उक्त घटना को कार्य करने वाले वाहन की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि मृतक मामूरा गांव से कुछ दिन पहले से लापता थे। उनके परिजनों ने थाना फेस -3 में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

थाना सेक्टर-20 के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि विजेंदर पुत्र शरीफ दयाल ने आज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बीती रात को उसकी चाची रामकुमार पत्नी हरिकिशन अड्डा पीर के पास से गुजर रही थी, तभी एक ई-रिक्शा चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए चाची को टक्कर मार दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। उन्हें उपचार के लिए नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि थाना पुलिस पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

आतिशी को लेकर सदन में हंगामा वीडियो की होगी एफएसएल जांच

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी की कथित टिप्पणी को लेकर गुरुवार को भी सदन में भाजपा विधायकों का हंगामा जारी रहा। दो बार विधानसभा को आधे घंटे के लिए जबकि तीसरी बार विधानसभा को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संबंधित मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए सौंपा है। उन्होंने वीडियो की एफएसएल जांच 15 दिन के भीतर पेश करने को कहा है ताकि सच्चाई सामने आ सके। एक दिन के लिए शीतकालीन सत्र को भी बढ़ाया गया है।

विधायी कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सदन में कहा कि विपक्ष द्वारा दो दिनों से कार्यवाही बाधित किए जाने के कारण सरकार का महत्वपूर्ण कार्य लंबित है। उन्होंने एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पारित करने और प्रदूषण पर चर्चा कराने का उल्लेख करते हुए सदन की अवधि एक दिन बढ़ाने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने संबंधित प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को भेजकर निर्धारित समय-सीमा में जांच कराने का भी निवेदन किया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी की वीडियो क्लिप की जांच स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब से होगी। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिए हैं कि संबंधित वीडियो क्लिप फॉरेंसिक विभाग को उपलब्ध कराए और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि नेता प्रतिपक्ष की वीडियो क्लिप में छेड़छाड़ की गई है। इसलिए सत्ता पक्ष की सहमति से उक्त वीडियो को जांच के लिए भेजा गया है। नेता प्रतिपक्ष को बार-बार सदन में बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपना पक्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसी कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए यह जांच कराई जा रही है। जरनैल सिंह को लेकर भी संज्ञान दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने विधायक हरीश खुराना द्वारा विधायक जरनैल सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना से संबंधित की गई शिकायत पर संज्ञान लिया है।

अध्यक्ष ने उक्त विषय को नियमों के अनुसार परीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है। आतिशी ने किया गुरुओं का अपमान दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि इस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना ने एक बहुत बड़ा पाप किया है।

उन्होंने गुरुओं का अपमान किया और इसके बाद वह सदन में नहीं आ रही हैं। अध्यक्ष ने कई बार उनको बुलाया, उसके बाद भी वो नहीं आई। उन्होंने कहा कि आतिशी की माफी से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने कल बयान जारी किया है, इसके बाद सदन उनकी सदस्यता रद्द करे।

आतिशी के बयान पर विधानसभा में सियासी तकरार जारी

नई दिल्ली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी की कथित टिप्पणी को लेकर गुरुवार को भी सियासी तकरार जारी रही। भाजपा विधायकों के हंगामे के चलते दो बार विधानसभा की कार्यवाही आधे-आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में सदन को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधायी कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सदन में कहा कि विपक्ष द्वारा पिछले दो दिनों से कार्यवाही बाधित किए जाने के कारण सरकार के महत्वपूर्ण कार्य लंबित हैं। उन्होंने एलजी के अभिभाषण पर प्रस्ताव पारित कराने और प्रदूषण पर चर्चा कराने का उल्लेख करते हुए सदन की अवधि एक दिन बढ़ाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने संबंधित प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को भेजकर निर्धारित समय-सीमा में जांच कराने का भी निवेदन किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने संबंधित मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। उन्होंने वीडियो की एफएसएल जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। साथ ही शीतकालीन सत्र की अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी गई। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी की वीडियो क्लिप की जांच स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब में कराई जाएगी। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिए कि संबंधित वीडियो क्लिप फॉरेंसिक विभाग को उपलब्ध कराई जाए और जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया था कि नेता प्रतिपक्ष की वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है। सत्ता पक्ष की सहमति से उक्त वीडियो को जांच के लिए भेजा गया है। अध्यक्ष ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष को बार-बार सदन में बुलाए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक अपना पक्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इसी कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए यह जांच कराई जा रही है।

प्रदूषण पर चर्चा के लिए एक दिन बढ़ाया गया दिल्ली विस का सत्र : सिरसा

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण जैसे गंभीर और जन-स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए विधानसभा सत्र एक दिन के लिए और बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने इस बात की सच्चाई आनी चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर पिछली सरकार ने 11 वर्षों तक क्या किया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार ने मात्र 11 महीनों में ठोस कदम उठाते हुए दिल्ली को अब तक के सबसे अधिक साफ दिन दिए हैं।

सिरसा ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी (आआपा) की सरकार प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। आज दिल्ली जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, वे वर्षों की नीतिगत असफलताओं, खोखले दावों और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति का परिणाम हैं। प्रदूषण के वास्तविक कारण और समयबद्ध समाधान जैसे पहलुओं पर विधानसभा में चर्चा जरूरी है।

सिरसा ने उम्मीद जताई कि विपक्ष इस चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखेगा और सरकार की बात भी सुनेगा।उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की नेता आतिशी पिछले दो दिनों से सदन से अनुपस्थित रही हैं, जबकि वे लगातार यह प्रश्न उठाती रही हैं कि प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। जब चर्चा का अवसर था, तब वे सदन में उपस्थित नहीं थीं। उन्होंने उनसे और विपक्ष के सभी विधायकों से कल प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर होने वाली विस्तृत चर्चा में हिस्सा लेने का आग्रह किया।

संक्षिप्त खबरें

यात्रियों से लूटपाट करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। मध्य जिला की आईपी स्टेट थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कम किराए का झांसा देकर यात्रियों से लूटपाट करता था। इस संबंध में पुलिस ने गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बस को जब्त कर यात्रियों से लूटी गई नकदी भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में शास्त्री पार्क निवासी योगेश, अरशद और प्रेमशंकर उर्फ अजय शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ बदमाश आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी के आसपास के इलाकों में एक निजी बस चला रहे हैं। वह यात्रियों को असामान्य रूप से कम किराया बताकर उन्हें बस में बैठाकर रास्ते में लूट लेते हैं। इसके बाद उन्हें आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले राजघाट और आसपास के इलाकों के सुनसान स्थानों पर छोड़ देते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष गश्त शुरू की और राजघाट रेड लाइट के पास बस को रोक लिया। रोकने के दौरान यात्रियों ने राहत की सांस ली और बताया कि बस के अंदर उनसे लूटपाट की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लूटी गई 1,850 रुपये की नकदी बरामद की गई और मामला दर्ज किया गया।

डॉ. शाहीन ने जेल में बंद पति से मिलने की अनुमति मांगी

नई दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट केस की आरोपी डॉ. शाहीन सईद ने न्यायिक हिरासत में अपने पति मुजम्मिल से मिलने के लिए याचिका दायर की है। वह भी इस मामले में सह-आरोपी हैं और न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। एनआईए की जांच के बाद दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्य जिला और सेशन जज (विशेष एनआईए) अंजू बजाज चंदना ने याचिका पर जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी है। शाहीन सईद की ओर से पेश वकील एम.एस. खान ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को अपने पति से मिलने की इजाजत दी जाए, जो उसी जेल में बंद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जेल के नियमानुसार अगर पति-पत्नी एक ही जेल में बंद हैं तो वह एक दूसरे से हफ्ते में एक दिन मिल सकते हैं। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी है और सेंट्रल जेल में बंद है और उसका पति मुजम्मिल भी इसी मामले में सह आरोपी है और सेंट्रल जेल, तिहाड़ में बंद है। याचिकाकर्ता ने संबंधित जेल अधीक्षक से अपने पति से मिलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जेल अधिकारियों ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

एनएसयूटी में आयोजित होगा स्टार्टअप महोत्सव

नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली को भारत की स्टार्टअप राजधानी बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में दिल्ली सरकार एक ठोस और दूरदर्शी रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत सरकार नौ जनवरी को नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, द्वारका में आयोजित होने वाले दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को एक मंच पर लाने का सशक्त प्रयास है, जिससे कैंपस-टू-मार्केट स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। युवा उद्यमिता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए, दिल्ली सरकार, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय (डीटीटीई) के माध्यम से महोत्सव का आयोजन कर रही है। यह एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य छात्र-नेतृत्व वाले प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को सशक्त बनाना तथा दिल्ली के कैंपस-टू-मार्केट स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत करना है।

भाजपा का आतिशी के कथित आपत्तिजनक बयान पर विरोध, आज आप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता व पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर सिख गुरु तेग बहादुर सिंह के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आतिशी तुरंत बिना शर्त माफी नहीं मांगतीं है तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। शुक्रवार को सुबह 11 बजे दिल्ली भाजपा सिख प्रकोष्ठ और अन्य कार्यकर्ता आप कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सिख गुरु तेग बहादुर सिंह का अपमान किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा के दौरान आतिशी द्वारा की गई टिप्पणी न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि आप की सिख विरोधी और समाज को बांटने वाली मानसिकता को उजागर करती है। सचदेवा ने इसे आप की देश की आस्था और संस्कृति को निशाना बनाने वाली सोच का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि आतिशी का बयान कोई भूल नहीं, बल्कि आप की उस मानसिकता का हिस्सा है जो पहले सनातन धर्म पर हमला करती रही और अब सिख समाज का अपमान कर रही है।

यह विकास की नहीं, समाज तोड़ने की राजनीति है। सचदेवा ने 6 जनवरी की रात तुर्कमान गेट मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई पत्थरबाजी की दिल्ली पुलिस से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स द्वारा भड़काने और सपा सांसद मोहिबुल्लाह नादवी की मौजूदगी में कोई साजिश तो नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए।

दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 5 आरोपी 13 दिन की न्यायिक हिरासत में

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी करने वाले पांच आरोपितों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पूजा सुहाग ने यह आदेश दिया। कोर्ट इन आरोपितों की जमानत याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा।

जिन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उनमें मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 11 आरोपितों को पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को छह और लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने जिन छह लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद शामिल हैं।

ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले हैं। सात एवं आठ जनवरी की दरमियानी रात को फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। इसके बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पथराव में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये। घायल पुलिसकर्मियों में इलाके का एसएसओ भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है। उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 200 लोग अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाने में शामिल थे।

अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रव के लिए सपा सांसद जिम्मेदार: जमाल सिद्दिकी

नई दिल्ली। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दिकी ने तुर्कमान गेट दिल्ली स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास उपद्रव के लिए रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को जिम्मेदार बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। गुरुवार को जारी की गई जानकारी के मुताबिक जमाल सिद्दिकी ने आरोप लगाया कि सपा सांसद ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों उकसाने का काम किया। जबकि मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार और वरिष्ठ स्थानीय नागरिक लोगों को समझाने का काम रहे थे, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं। ऐसे में सपा सांसद का वहां पहुंच कर पत्थरबाजों का समर्थन करना, मौजूद लोगों को भड़काना पूर्व नियोजित था, जिसकी योजना लखनऊ में बनाई गई।

दिल्ली के कापसहेड़ा में प्लास्टिक के ढेर में आग लगी

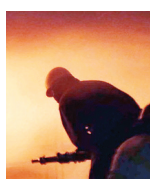

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कापसहेड़ा में बृहस्पतिवार तड़के प्लास्टिक के ढेर में आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग (डीएफएस) ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की सूचना तड़के चार बजकर 11 मिनट पर मिली, जिसके बाद दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर भेजी गयीं। उन्होंने बताया कि हमने दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर भेजीं, जिन्होंने सुबह सात बजकर 20 मिनट पर आग पर काबू पा लिया।

दिल्ली पुलिस ने अवैध गारमेंट यूनिट का भंडाफोड़ किया

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जिला जांच इकाई (डीआईयू) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध गारमेंट निर्माण और भंडारण इकाई का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के नाम पर तैयार किए जा रहे 1,919 नकली रेडीमेड परिधानों को जब्त किया गया है। जब्त किए गए कपड़ों में कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के नकली उत्पाद शामिल हैं। पुलिस की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि यह कार्रवाई टोडापुर, दिल्ली में स्थित एक अपर-ग्राउंड प्रिमाइस पर की गई, जहां बड़े पैमाने पर नकली ब्रांडेड कपड़ों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान राजीव नागपाल (45) के रूप में हुई। यह पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ब्रांड्स के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पश्चिमी दिल्ली में बड़े पैमाने पर नकली कपड़ों का निर्माण और बिक्री की जा रही है। शिकायत की गहन जांच, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दस्तावेजों के सत्यापन एवं ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 की धारा 115(4) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स से अनिवार्य राय प्राप्त करने के बाद, डीआईयू वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने छापेमारी की योजना बनाई।

महिला व बच्चों के विकास को लगेंगे पंख मंत्रालय ने लॉन्च किया 'पंखुड़ी' पोर्टल

❖ जनभावना टाइम्स

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को 'पंखुड़ी' नामक एकीकृत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) एवं साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ी पहलों में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारक भागीदारी को मजबूत करना है।

मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पंखुड़ी पोर्टल पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने प्रौद्योगिकी, सरकार और नागरिकों के बीच सेतु पर बनाने पर जोर दिया। यह पोर्टल पारदर्शिता, सहभागिता और विश्वास को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को सफल बनाने में जन भागीदारी जरुरी है। पंखुड़ी पोर्टल इसी दृष्टि को साकार करता है, जो सरकार, नागरिकों और संस्थानों का सामाजिक विकास का साझा डिजिटल मंच है। उन्होंने कहा कि पंखुड़ी को एक सिंगल-विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जो व्यक्तियों, प्रवासी भारतीयों, गैर-सरकारी संगठनों, सीएसआर योगदानकर्ताओं, कॉर्पोरेट संस्थाओं और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में कार्यरत सरकारी एजेंसियों को एक साथ जोड़ता है।

अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से लोग पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बाल कल्याण, संरक्षण एवं पुनर्वास, तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे प्रमुख विषयों में स्वैच्छिक एवं संस्थागत योगदान कर सकते हैं। यह पोर्टल सीएसआर और स्वैच्छिक योगदान के लिए एक साझा डिजिटल इंटरफेस प्रदान कर विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर अभिसरण और समन्वय सुनिश्चित करता है। इससे महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और जवाबदेही में सुधार होता है। इस मौके पर राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तथा मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक भी उपस्थित रहे।

क्या है पंखुड़ी पोर्टल

मंत्रालय के प्रमुख मिशनों- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था है। इस पोर्टल से योगदानकर्ता पोर्टल पर पंजीकरण कर पहलें चुन सकते हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और स्पष्ट स्वीकृति प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने योगदान की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पोर्टल के माध्यम से सभी योगदान केवल गैर-नकद माध्यमों से स्वीकार किए जाते हैं। यह प्लेटफॉर्म केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों, क्रियान्वयन एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से देशभर में 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों, 5,000 बाल देखभाल संस्थानों, लगभग 800 वन स्टॉप सेंटर, 500 से अधिक शक्ति निवास और 400 से अधिक शक्ति सदन में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार होगा, जिससे इन संस्थानों से सेवाएं प्राप्त करने वाले करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

संपादकीय

भारत को घुड़की न दें

अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को भी घुड़काना शुरू कर दिया है। बेशक वह भारत में 'वेनेजुएला प्रयोग' को दोहराने का दुस्साहस नहीं कर सकते, क्योंकि वह भारत की चौतरफा ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। भारत की ईमानदारी और प्रतिबद्धताओं को भी समझते हैं। भारत एक प्रमाणित परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है, अमरीका से अधिक यह कौन जानता है, क्योंकि अमरीका ने भारत के साथ असैन्य परमाणु करार कर रखा है। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान आया है-'दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इनसान हैं। वे जानते हैं कि मैं इससे (रूस से तेल खरीद) खुश नहीं हूं और मुझे खुश रखना जरूरी है। यदि रूस से तेल खरीद जारी रही, तो भारत पर बहुत जल्दी और टैरिफ लग सकते हैं। वह भारत के लिए ठीक नहीं होगा।' गौरतलब यह है कि भारत अप्रैल, 2025 में रूस से 8.6 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदता था, जो नवंबर तक घट कर 7.7 मिलियन टन हो गया। भारत अमरीका से भी करीब 3 मिलियन टन तेल खरीदता है। अमरीका की तुलना में रूस से तेल खरीद आज भी अधिक है। भारत ने किसी दबाव में तेल खरीद को कम नहीं किया, यह उसकी जरूरतों के मुताबिक है। तेल भंडारों और क्षमताओं को लेकर अमरीका का स्थान बहुत नीचे है। वेनेजुएला में सबसे अधिक प्रमाणित 303 अरब बैरल तेल के भंडार हैं और वह आज भी सबसे बड़ा सप्लायर है। उसके बाद सऊदी अरब और ईरान सबसे अधिक तेल बेचते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पूरी रणनीति तेल कारोबार पर वर्चस्व स्थापित करने की है, जिसका विरोध अमरीका में ही किया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वेनेजुएला हमले और वहां के राष्ट्रपति को अगवा करके अमरीका लाने के ऑपरेशन को लेकर ट्रंप के खिलाफ आक्रामक बयान दिए हैं। उन्हें 'राजनीतिक' भी माना जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने पर भी चर्चा छिड़ चुकी है। डेमोक्रेट्स और ट्रंप की पार्टी के सांसद अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें पद से हटाने की राजनीति में जुट गए हैं। जहां तक टैरिफ का मामला है, वह अमरीकी अदालत के विचाराधीन है, लिहाजा ट्रंप नए टैरिफ नहीं थोप सकते। अलबत्ता अमरीकी राष्ट्रपति कमोबेश भारत को घुड़कियां देने से बाज जरूर आएं। यदि उन्होंने घोषित 50 फीसदी से अधिक टैरिफ थोपने का कोई फैसला लिया, तो अमरीकी कांग्रेस (संसद) उसे खारिज कर सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप बड़बोले नेता हैं, लिहाजा उनकी टिप्पणियों पर हर बार पलटटिप्पणी भारत करे, ऐसा संभव नहीं है और न ही भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को ट्रंप के बयानों की चिंता करनी चाहिए। भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ थोपने के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 8 फीसदी से अधिक रही है। सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और प्रमुख रेटिंग एजेंसियों के आकलन हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7 फीसदी से अधिक रहेगी। टैरिफ के बावजूद भारत की जीडीपी 375 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढने वाली अर्थव्यवस्था है।

प्रवासी भारतीय और 2047 का संकल्प

प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्यों की यदि बात करें तो इसमें क्रमशः विश्व में बसे भारतीयों द्वारा भारत के विकास और समाज में दिए योगदान को सम्मानित करना, भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच सम्बन्धों को मज़बूत करना, एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ प्रवासी भारतीय अपनी राय, अनुभव और सुझाव साझा कर सकें तथा प्रवासी भारतीय सम्मान(अवार्ड) जैसे पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करना है। गौरतलब है कि यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सम्मान है जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है, जो विदेश में रहते हुए भारत और भारतीय समुदाय के लिए विशिष्ट योगदान देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रवासी भारतीय दिवस के प्राथमिक लक्ष्य भारत और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण करना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में प्रवासी भारतीयों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना है। साथ ही, यह विश्व समुदाय के बीच भारत की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करते हुए विदेशों में भारत के प्रति बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास करता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के समर्थन को बढ़ावा देता है और विश्वभर में स्थानीय भारतीय समुदायों के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।

-सुनील कुमार महला-

हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे एन आर आई दिवस(नोन-रेजिडेंट इंडियन डे) भी कहा जाता है। पाठकों को बताता चलूं कि इस दिन को इसलिए चुना गया था, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी। यदि हम यहां पर इस दिवस के इतिहास की बात करें तो यह दिवस साल 2003 से मनाया जा रहा है, जब पहली बार भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों के योगदान को सम्मान देने के लिए इसे आयोजित किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स) द्वारा आयोजित होता है।

प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्यों की यदि बात करें तो इसमें क्रमशः विश्व में बसे भारतीयों द्वारा भारत के विकास और समाज में दिए योगदान को सम्मानित करना, भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच सम्बन्धों को मज़बूत करना, एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ प्रवासी भारतीय अपनी राय, अनुभव और सुझाव साझा कर सकें तथा प्रवासी भारतीय सम्मान(अवार्ड) जैसे पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित करना है। गौरतलब है कि यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सम्मान है जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है, जो विदेश में रहते हुए भारत और भारतीय समुदाय के लिए विशिष्ट योगदान देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रवासी भारतीय दिवस के प्राथमिक लक्ष्य भारत और विदेशों में बसे भारतीयों के बीच एक सशक्त सेतु का निर्माण करना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में प्रवासी भारतीयों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करना है। साथ ही, यह विश्व समुदाय के बीच भारत की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करते हुए विदेशों में भारत के प्रति बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास करता है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के समर्थन को बढ़ावा देता है और विश्वभर में स्थानीय भारतीय समुदायों के कल्याण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रवासी भारतीयों को अपनी पैतृक भूमि की सरकार और जनता से भावनात्मक व वैचारिक रूप से जुड़ने का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है, जिससे पारस्परिक सहयोग और विश्वास और अधिक मजबूत होता है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि साल 2003 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और उसके बाद अन्य शहरों में भी पारंपरिक रूप से इसका आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तहत प्रवासी भारतीय समुदाय को मान्यता देने एवं उनके साथ जुड़ने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2015 में इसे दो साल में एक बार आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक दो साल में 9 जनवरी को मनाया जाने वाला प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) एक उल्लेखनीय आयोजन है जिसके तहत भारतीय प्रवासियों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिये दिये गए योगदान पर प्रकाश डाला जाता है। पिछले साल यानी कि वर्ष 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम-विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान रखी गई थी तथा इसका आयोजन ओडिशा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 तक किया गया था। इस साल 9 जनवरी 2026 को सांकेतिक रूप से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए यह आलेख लिखे जाने तक किसी विशेष थीम की आधिकारिक घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई है।

बहरहाल, यदि हम यहां पर प्रवासी भारतीयों के योगदान की बात करें तो प्रवासी भारतीय विकसित भारत के निर्माण में आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक सेतु के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। वे न केवल भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजकर अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और स्टार्टअप फंडिंग के माध्यम से नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशों में अर्जित अपने तकनीकी ज्ञान और अनुभव (ब्रेन गेन) को भारतीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझा करके वे कौशल विकास(स्किल डेवलपमेंट) में भी मदद कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने और भारतीय उत्पादों के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार तैयार करने में भी उनकी भूमिका निर्णायक है।

अंततः, अपनी मातृभूमि के साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव और वैश्विक नेटवर्किंग भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की गति को तेज कर सकती है। हालांकि, प्रवासी भारतीयों से संबंधित अनेक चुनौतियां भी विद्यमान हैं। मसलन, प्रवासी भारतीयों से संबंधित चुनौतियों को संक्षेप में देखें तो प्रमुख समस्या प्रशासनिक जटिलता और कानूनी बाधाओं की है, जहाँ भारत में निवेश या संपत्ति प्रबंधन के दौरान उन्हें लालफीताशाही और लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कई देशों में प्रवासियों को नस्लभेद, कार्यस्थल पर असुरक्षा और कड़े वीजा नियमों जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। दूसरी ओर, भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान न होना भी प्रवासियों की नई पीढ़ी को पूरी तरह जुड़ने से रोकता है। बहरहाल, यहां जानकारी देना चाहूंगा कि प्रवासी भारतीयों की सहायता और उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने दो मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मदद पोर्टल तथा ई-माइग्रेट पोर्टल तैयार किए हैं। मदद पोर्टल की बात करें तो यह विदेश मंत्रालय की एक प्रभावी ऑनलाइन समाधान प्रणाली है, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों की आपातकालीन शिकायतों का निवारण करना है। यदि किसी प्रवासी भारतीय को विदेश में कानूनी समस्या, पासपोर्ट खोने, घरेलू उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है, तो वे इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि शिकायतों की निगरानी सीधे उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है और समाधान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है। वहीं दूसरी ओर ई-माइग्रेट पोर्टल मुख्य रूप से उन भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है जो रोजगार के लिए विदेश (विशेषकर खाड़ी देशों) जाते हैं। यह विदेशी नियोक्ताओं और भर्ती एजेंटों के डेटाबेस को एकीकृत करता है, जिससे श्रमिकों को फर्जी एजेंटों और शोषण से बचाया जा सके। इसके माध्यम से श्रमिक अपनी बीमा पॉलिसी (प्रवासी भारतीय बीमा योजना) और अपने रोजगार अनुबंध की वैधता की जांच आसानी से कर सकते हैं। आगे की राह के रूप में, भारत को प्रवासियों के लिए सिंगल विंडो डिजिटल सिस्टम और विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनके संपत्ति विवाद जल्द सुलझ सकें। साथ ही, नमन जैसे पोर्टल्स के जरिए उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण और नो इंडिया प्रोग्राम जैसे सांस्कृतिक अभियानों के माध्यम से युवा पीढ़ी को जड़ों से जोड़ना आवश्यक है।

सरकार को वैश्विक स्तर पर उनके अधिकारों के लिए सक्रिय कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वे बिना किसी भय के विकसित भारत के विजन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। निष्कर्षतः, हम यह बात कह सकते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस केवल एक वार्षिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय और उनकी मातृभूमि के बीच के गहरे भावनात्मक और रणनीतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का एक सशक्त मंच है। यह दिवस प्रवासियों की उपलब्धियों का सम्मान करने के साथ-साथ उन्हें विकसित भारत 2047 के संकल्प में सक्रिय भागीदार बनाने का अवसर प्रदान करता है। प्रवासी भारतीय अपनी पूंजी, तकनीकी विशेषज्ञता और वैश्विक प्रभाव के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक जीवंत सेतु (लिविंग ब्रिज) का कार्य कर रहे हैं। अंततः, उनकी सक्रिय सहभागिता ही भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कुंजी है।

सुप्रीम कोर्ट का उपद्रवियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नजरिया

-मनोज कुमार अग्रवाल-

दिल्ली के दंगाइयों को शीर्ष अदालत ने राहत देने से सीधा इंकार कर दिया यह अदालत की अराजकता से निबटने की जीरो टॉलरेंस को नीति का हवाला देता है। उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से साफ इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने साथ ही उमर खालिद और शरजील इमाम पर इस मामले में एक साल तक जमानत याचिका दाखिल करने पर भी रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बैंच ने हालांकि इस मामले में अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है।

इस मामले में बैंच ने कहा, अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं। इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है। कार्यवाही के इस चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों को जमानत मिली है, उनकी भूमिका सीमित और परिस्थितिजन्य मानी गई है, जबकि उमर खालिद और शरजील इमाम पर दंगों की साजिश रचने, भीड़ को भड़काने और सुनियोजित तरीके से हिंसा को दिशा देने के गंभीर आरोप हैं। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखा जाये तो उच्चतम न्यायालय का यह फैसला केवल दो व्यक्तियों की जमानत याचिका का निपटारा नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय संकल्प का स्पष्ट संदेश है।

आपको पता रहे उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोग कोई साधारण आरोपी नहीं हैं। ये वह चेहरे हैं जिन्होंने विचारधारा की आड़ में सड़कों पर आग लगाने की मानसिकता को खाद पानी दिया। यह साबित हो चुका है कि दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे। उनके पीछे शब्दों के बारूद, भाषणों की चिंगारी और योजनाबद्ध उकसावे की लंबी तैयारी थी। ऐसे मामलों में यदि अदालत नरमी दिखाती, तो यह न केवल न्याय के साथ अन्याय होता बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक संकेत भी जाता। अदालत ने सही कहा कि इन दोनों की स्थिति अन्य आरोपियों से अलग है। यह अंतर केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। दंगा केवल पत्थर फेंकने से नहीं होता, दंगा उस सोच से पैदा होता है जो समाज को बांटने का काम करती है। जब किसी मंच से यह कहा जाए कि सड़कों पर उतर कर व्यवस्था को जाम कर दो, तब वही शब्द बाद में आग वन जाते हैं।

जमानत खारिज करने का फैसला उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं। यह फैसला बताता है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अराजकता फैलाने की छूट नहीं है। मुकदमे में देरी को लेकर अदालत की टिप्पणी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्षों से एक तर्क गढ़ लिया गया था कि अगर मुकदमा लंबा चल रहा है, तो आरोपी को स्वतः राहत मिलनी चाहिए। यह सोच न्याय व्यवस्था को कमजोर करती है। अगर गंभीर साजिशों में केवल समय के आधार पर जमानत मिलने लगे, तो हर देश विरोधी ताकत समय को हथियार बना लेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उपद्रवी और दंगाई मानसिकता वाले लोगों पर पड़ेगा। अब यह भ्रम टूटेगा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया अंततः उन्हें बचा लेगी। देखा जाये तो अदालत का सख्त रुख भारत की आतंकवाद के खिलाफ चल रही लढाई को मजबूत करता है।

आपको बता दें यह फैसला उन आम नागरिकों के लिए भी भरोसे का आधार है जिन्होंने दंगों में अपने घर, दुकानें और परिजन खोए। उनके लिए न्याय केवल सजा नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग इसे कठोरता कहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठोर फैसले जरूरी होते हैं। उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की न्यायपालिका आज भी राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और संविधान की मूल भावना को समझती है। यह फैसला आने वाले समय में न केवल कानूनी मिसाल बनेगा, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी भी होगा जो भारत को भीतर से तोड़ने का सपना देखती हैं। यह निर्णय बताता है कि भारत कमजोर नहीं है, भारत चुप नहीं है और भारत अब दंगों की राजनीति को वर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हालिया कानूनी घटनाक्रमों और न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, खुद को एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी बताकर कानून से ऊपर समझने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्ती बढ़ी है। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि एक्टिविस्ट या बुद्धिजीवी होने का लेबल किसी व्यक्ति को आपराधिक जांच या कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। पिछले कुछ वर्षों में भीमा कोरेगांव और दिली दंगों जैसे मामलों में कई चर्चित चेहरों की गिरफ्तारियों और अदालतों द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने को इस दिशा में एक बड़ा झटका माना गया है। जांच एजेंसियों ने इन पर अर्बन नक्सल या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत की गई कार्रवाई और अदालतों द्वारा साक्ष्यों के आधार पर दी गई कड़ी टिप्पणियों ने यह संदेश दिया है कि वैचारिक स्वतंत्रता की आड़ में हिंसा या अस्थिरता को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में कहा है कि विरोध का अधिकार मौलिक है, लेकिन यह कानून के शासन के उल्लंघन का अधिकार किसी को नहीं देता है।

जाहिर है कि कानून का शासन बनाए रखने के लिए अदालत का भी सख्त रुख होना अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके बिना सामूहिक गुंडई अराजकता फैलाने और भीड़ तंत्र कायम करने के षडयंत्रों पर नकेल डालना संभव नहीं होगा।

ऐसे पहचानें आपकी कुंडली में कौन से ग्रह हैं कमजोर

कुछ सामान्य बातें हैं, जिनका ध्यान रखा जाए तो अंदाज लगाया जा सकता है कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की क्या स्थिति है। फिर उनके लिए उपाय भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति की कुंडली में राहु जहां भी होगा, वहां उस भाव से सरोकार रखने वाली चीजें और स्थितियां असुरक्षित होंगी। राहु से सातवें स्थान पर रहने वाला केतु जिस भाव में होता है, उस विशेषताओं से जातक खुद को अलग करना चाहता है।

कुंडली में सूर्य की कमजोर स्थिति आत्म-विश्वास को कमजोर करती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों में घबराता है। कमजोर चंद्रमा निर्णय को लेने में रुकावट खड़ी करता है। छोटी-छोटी मामूली बातें भी जातक को बुरी तरह परेशान कर देती है। निर्णय लेते समय भूल भटक जाने की स्थिति कमजोर मंगल की ओर संकेत करती है। क्रोध में अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहना भी मंगल के प्रतिककूलता का प्रभाव होता है।

भाई-बहनों से बिगड़े हुए संबंध, त्वचा की परेशानी का होना, निर्णय लेते वक्त कई तरह के मुसीबतों का आना आपके आदि आपके बुध के बुरे हाल की तरफ इशारा करता है। अच्छे सलाहकार का अभाव, पिता अथवा पिता-तुल्य लोगों से मार्ग-दर्शन का न मिलना कमजोर गुरु की तरफ इशारा करता है।

भौतिकदृसुखों में बार-बार बाधा का आना, राग और प्रेम में विफलता शुक्र का पीड़ति बताती है। शनि का नाम भय और आतंक के साथ लिया जाता है। लेकिन यह एक अनुशासित ग्रह है तथा हमारे कर्मों का फल निश्चित और यथाशीघ्र देता भी है। यदि कोई व्यक्ति अपने किए हुए वायदों पर खरा नहीं उतरता है, अपने सेवकों से संबंध ठीक नहीं हैं तो अर्थ है कि शनि कमजोर स्थिति में बैठा है। ग्रहों की स्थिति जानकर अगर हम अपेक्षित दिशा में लगातार सकारात्मक प्रयास करते रहे तो जो भी होगा वह शुभ ही होगा।

आज का इतिहास

1718 - फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की।
1721 - इंग्लैंड में दक्षिण सागर बुलबुले की जांच की समिति इसके निष्कर्ष प्रकाशित किया।
1768 - फिलिप अस्स्टली ने लंदन में पहले आधुनिक सर्कस का आयोजन किया।
1771 - सम्राट गो-मोमोज़ोनो ने अपनी मासी के अपहरण के बाद जापान के सिंहासन को स्वीकार किया।
1792 - जेसी की संधि रूसी साम्राज्य के युद्ध को समाप्त किया, जो कि क्रोएमी के ऊपर तुर्क साम्राज्य के साथ थी।
1799 - ब्रिटिश प्रधान मंत्री विलियम पिट ने युवा नेपोलियन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए आयकर का परिचय दिया।
1854 - जर्मन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पिट्सबर्ग, यू.एस.ए. में टेउटोनिया बाज़ारिया की स्थापना की गई।
1855 - क्लैपर गाइडिंग स्टार अटलांटिक सागर में गायब गया जिसमें 480 लोग मरे गए।
1873 - 19वीं शताब्दी के सबसे साहसी यूरोपीय शासकों में गिने जाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय का निधन हुआ।
1878 - अम्बर्टो आई इटली का राजा बनाया गया।
1936 - एक भूकंप,कोलंबिया में 250 लोग मारे गए।
1941 - यूरोपीय देश रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में छह हजार यहूदियों की हत्या हुई।
1945 - बेस्टांग दर्रा की लड़ाई मनीला के उत्तर में शुरू हुई।
1951 - अमेरिका के न्यूयॉर्क में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय खुला।
1960 - मिस्र में नील नदी पर आसवान नामक बांध का निर्माण आरंभ हुआ।
1962 - क्यूबा और सोवियत संघ ने एक व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किया।
1974 - हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, गीतकार, गायक और अभिनेता फरहान अख्तर का जन्म हुआ।

अवैध कब्जे और बेघर होता भारतः एक अंतहीन राष्ट्रीय संकट

-ललित गर्ग-

सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की समस्या भारत में न तो नई है और न ही किसी एक क्षेत्र तक सीमित। यह एक ऐसी जटिल और बहुआयामी चुनौती है, जो शहरीकरण, पलायन, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक मजबूरियों के सम्मिलित परिणाम के रूप में सामने आती है।

देश के लगभग हर राज्य, हर बड़े शहर और अनेक कस्बों में सरकारी जमीन पर मकान, दुकानें, झुग्गियां, गोदाम, यहां तक कि बड़े-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान और संस्थान खड़े मिल जाते हैं। वर्षों तक यह सब कुछ खुलेआम होता रहता है, लेकिन जिम्मेदार तंत्र या तो आंखें मूंदे रहता है या जानबूझकर चुप्पी साधे रहता है। जब अचानक विकास परियोजनाओं, सड़क चौड़ीकरण, रेलवे, मेट्रो, औद्योगिक गलियारों या स्मार्ट सिटी योजनाओं की जरूरत सामने आती है, तब सरकार की नींद खुलती है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होती है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा संकट उन लोगों पर टूटता है, जो वर्षों से वहां रह रहे होते हैं और जिनका जीवन, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य उसी जमीन से जुड़ चुका होता है। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क जैसे संगठनों के आंकड़े इस समस्या की भयावहता को उजागर करते हैं। वर्ष 2017 से 2023 के बीच साढ़े तीन लाख से अधिक मकानों पर बुलडोजर चलाए गए और करीब सोलह लाख लोग बेघर हुए। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में लगभग 1.7 करोड़ लोग ऐसे दायरे में हैं, जिनके घर विकास परियोजनाओं या अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के कारण टूट सकते हैं। इनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिन्होंने अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर घर बनाए, बच्चों को स्कूल में डाला, आसपास रोजगार तलाशा और एक स्थायी जीवन की कल्पना की। जब ये घर टूटते हैं तो केवल दीवारें नहीं गिरतीं, बल्कि पूरे परिवार की सामाजिक और आर्थिक संरचना ढह जाती है।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्रायः एक आवश्यक प्रशासनिक कदम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसके मानवीय पक्ष को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बेघर होना केवल सिर से छत छिनने की समस्या नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की संभावनाओं पर सीधा प्रहार है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूट जाती है, महिलाएं असुरक्षा और अस्थिरता के भय में जीने लगती हैं, बुजुर्ग इलाज और सहारे से वंचित हो जाते हैं और पुरुष वर्ग बेरोजगारी तथा मानसिक तनाव से जूझने लगता है। पुनर्वास योजनाएं कागजों पर तो आकर्षक लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वे या तो अधूरी होती हैं या इतनी दूरस्थ जगहों पर लागू की जाती हैं कि वहां रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है। इस पूरी समस्या का एक कड़वा सच यह भी है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एक दिन या एक रात में नहीं हो जाता। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रशासनिक उदासीनता, स्थानीय स्तर पर मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण की बड़ी भूमिका होती है। जब गांवों से पलायन कर गरीब परिवार शहरों की ओर आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले सस्ती या खाली जमीन की तलाश होती है। सरकारी जमीन इस दृष्टि से सबसे आसान निशाना बनती है। पहले अस्थायी झोपड़ियां खड़ी होती हैं, फिर धीरे-धीरे पक्के मकान, दुकानें और अन्य निर्माण होने लगते हैं। सरकारी एजेंसियां एवं जिम्मेदार तो तब ही हरकत में आते हैं जब या तो कोई हादसा होता है या फिर विकास कार्यों के दौर में इन्हें हटाने की जरूरत पड़ती है। महज सात साल में 16 लाख लोगों के बेघर होने का आंकड़ा छोटा नहीं है। इनमें भी 58 प्रतिशत से ज्यादा के बेघर होने की वजह अतिक्रमण ही है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की मिलीभगत से अनदेखी होती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। बिजली, पानी, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसी सुविधाएं भी किसी न किसी रास्ते से मिल जाती हैं, जिससे यह अतिक्रमण धीरे-धीरे 'वैधता' का भ्रम पैदा करने लगता है।

इस पूरी प्रक्रिया में भू-माफिया की भूमिका भी बेहद खतरनाक है। वे सरकारी जमीनों की पहचान कर गरीबों को वहां बसाते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं और बाद में राजनीतिक संरक्षण के जरिए उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। चुनाव आते ही ये बस्तियां वोट बैंक में बदल जाती हैं। इस राजनीतिक खेल में न तो कानून की प्रतिष्ठा बचती है और न ही आम नागरिकों का भविष्य सुरक्षित रहता है। अतिक्रमण हटाने के बाद होने वाले नुकसान को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो यह केवल प्रभावित परिवारों का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे देश का नुकसान है। एक ओर लोग अपने सीमित संसाधनों से घर बनाते हैं, दूसरी ओर सरकार अतिक्रमण हटाने पर भारी खर्च करती है। यदि शुरुआत में ही सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, समय पर निगरानी हो और अवैध कब्जे को बढ़ने से रोका जाए, तो यह दोहरा नुकसान टाला जा सकता है। दुर्भाग्य से हमारे यहां किसी परियोजना की घोषणा और उसके क्रियान्वयन के बीच लंबा अंतराल रहता है, जिसका फायदा अतिक्रमणकारी उठाते हैं। वर्षों तक जमीन खाली पड़ी रहती है और देखते ही देखते वहां एक पूरी बस्ती खड़ी हो जाती है।

विकास के लिए कई बार राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए विध्वंस की कार्रवाई जरूरी हो जाती है। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए केवल बुलडोजर चलाना पर्याप्त नहीं है। जरूरत एक ऐसी दूरदर्शी नीति की है, जिसमें अतिक्रमण रोकने की व्यवस्था शुरुआत से ही सख्त और प्रभावी हो। सरकारी जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड, नियमित सर्वेक्षण, स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई इस दिशा में जरूरी कदम हो सकते हैं। साथ ही शहरी गरीबों के लिए सस्ती आवास योजनाओं को वास्तविक जरूरतों के अनुरूप और रोजगार के करीब लागू करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि वे मजबूरी में अवैध कब्जे की ओर न जाएं। राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे पर ईमानदार आत्ममंथन करना होगा। वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अतिक्रमण को संरक्षण देना अंततः समाज और शासन दोनों के लिए घातक सिद्ध होता है।

यदि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से हो और अवैध कब्जे को किसी भी स्तर पर समर्थन न मिले, तो ऐसी स्थितियां स्वतः कम होंगी। सरकारी भूमि जनता की साझा संपत्ति है और इसका उपयोग योजनाबद्ध विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए होना चाहिए, न कि अव्यवस्था और अवैध कब्जों के लिए। अंततः सवाल यही है कि क्या हम समस्या के मूल कारणों पर गंभीरता से विचार करेंगे या हर बार बुलडोजर के बाद कुछ दिनों की संवेदना दिखाकर आगे बढ़ जाएंगे। यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया, तो आने वाले वर्षों में बेघर होने वालों की संख्या और बढ़ेगी, सामाजिक असंतोष गहराएगा और विकास का दावा खोखला साबित होगा। जरूरत इस बात की है कि सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल और समाज मिलकर इस जटिल समस्या का मानवीय, न्यायपूर्ण और दूरगामी समाधान तलाशें, ताकि विकास भी हो और किसी का जीवन उजड़ने से भी बच सके।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर -7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व बी-142/2, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 से प्रकाशित।
संपादकीय एवं संपर्क कार्यालय ए-152 सेक्टर-63, नोएडा-201301 **संपादक - आदित्य वशिष्ठ** कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा आर.एन.आई. DELHIN/2012/42452
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे। e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज योजना जल्द : नितिन गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए एक कैशलेस इलाज योजना जल्द शुरू करेगी। इसके तहत दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले भले इंसान को 25 हजार रुपये का इनाम भी मिलेगा और पीड़ित को अस्पताल में सात दिन तक रहने पर 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।

इलाज का खर्च इंश्योरेंस कंपनियां वहन करेंगी और जहां इंश्योरेंस नहीं होगा वहां सरकार रोड सेफ्टी फंड से खर्च उठाएगी। गडकरी ने यहां गुरूवार को देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों की सालाना बैठक की। बैठक में सड़क सुरक्षा, यात्रियों और आम लोगों की सुविधा, व्यापार करने में आसानी और ऑटोमोबाइल नियमों, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, हिट एंड रन पीड़ितों को मुआवजा, ई-डीएआर, सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, सड़क सुरक्षा अभियान, स्क्रैपिंग पॉलिसी, बस बॉडी कोड, दिव्यांगजनों के लिए सुगमता, बीएनसीएपी 2.0, ट्रकों और बसों में एडीएएस और मोटर व्हीकल एक्ट में प्रस्तावित संशोधन जैसे 12 विषयों पर चर्चा की गई। गडकरी ने कैशलेस इलाज योजना पर राज्यों की तैयारियों की समीक्षा कर उन्हें सक्रिय रूप से कमियों को दूर करने के लिए आगाह गया।

उन्होंने बताया कि असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत परिवहन एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करीबी और लगातार तालमेल जरूरी है। नीतियों में सामंजस्य, सहकारी संघवाद को मजबूत करने और देशभर में सुरक्षित, कुशल और नागरिक-केंद्रित परिवहन समाधान देने के लिए नियमित सलाह-मशविरा आवश्यक है। नई ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी का भी उल्लेख किया जो 15 जनवरी 2025 को शुरू की गई थी। पहले सात साल में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने में कठिनाइयां आईं और मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर दो साल तक रोक भी लगाई थी लेकिन नई योजना के बाद एक ही साल में 44 केंद्र स्थापित किए गए और 87 पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा मीटिंग में देश के 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1.85 लाख हिट एंड रन मामलों पर चर्चा की गई।

इसमें अब तक 12,273 दावे निपटाए गए हैं। गडकरी ने राज्यों से अपील की कि वे इस नीति के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और दावों की प्रक्रिया को तेज करें। मुआवजे की राशि बढ़ाकर गंभीर चोट के मामलों में 50 हजार रुपये और मृत्यु के मामलों में दो लाख रुपये कर दी गई है। गडकरी ने कहा कि जीरो फेटालिटी डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत 100 जिलों की सूची जारी की गई है जहां दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है। इन जिलों में वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। नागपुर, उन्नाव और कामरूप में इस कार्यक्रम से पहले ही बड़ी सफलता मिली है।

बैठक में दिव्यांगजनों के लिए सुगमता पर निर्णय लेते हुए सभी सिटी बसें दिव्यांगजन-फ्रेंडली बनाने पर चर्चा की गयी। इनमें लो फ्लोर हाइट, हाइड्रोलिक नीलिंग, व्हीलचेयर, लिफ्ट, रैंप और सहायक हैंडल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। बस बॉडी कोड पर भी चर्चा हुई। पिछले तीन महीनों में छह बस दुर्घटनाओं में 145 लोगों की मौत हुई। खराब डिजाइन और घटिया सामग्री को जिम्मेदार माना गया। संशोधित बस बॉडी कोड एक सितंबर 2025 से लागू हुआ है, लेकिन इसके बाद भी कुछ समस्याएं सामने आईं।

अब निर्णय लिया गया है कि स्लीपर कोच बसें केवल ऑटोमोबाइल कंपनियां ही बनाएंगी और मौजूदा बसों में फायर डिटेक्शन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी लाइटिंग और ड्राइवर ड्रोसिनेस इंडिकेटर जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों पर भी चर्चा कर सड़क सुरक्षा सुधार, व्यापार में आसानी, नागरिक सेवाएं, बेहतर नियम, गतिशीलता, उत्सर्जन नियम और परिभाषाओं को सरल बनाने जैसे विषय शामिल हैं।

गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत दिसंबर 2025 तक 3.94 लाख वाहनों को स्क्रैप किया गया है। इसमें 1.65 लाख सरकारी और 2.29 लाख निजी वाहन शामिल हैं। निजी क्षेत्र ने 2700 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे 40 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व और 70 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित हुए हैं। मंत्री गडकरी ने कहा कि वाहन-से-वाहन संचार तकनीक को भी लाने पर विचार किया जा रहा है। इससे गाड़ियां वायरलेस तरीके से एक-दूसरे से जुड़कर गति, स्थान, ब्रेकिंग जैसी जानकारी साझा करेंगी। इससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी और ब्लाइंड स्पॉट में मौजूद वाहनों की पहचान हो सकेगी। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 30 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपयोग की अनुमति सिद्धांत रूप में दी है।

वीबी-जी राम जी अधिनियम को लेकर कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है: प्रहलाद जोशी

बेंगलुरु। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वीबी-जी राम जी के बारे में दुष्प्रचार कर गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता और खामियों को उजागर करने के लिए 'वीबीजी रामजी अधिनियम' को लाया गया है, जिससे कांग्रेस को परेशानी है।

गुरुवार को बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर इस योजना के बारे में जानबूझकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'वीबीजी राम जी अधिनियम' में एआई तकनीक और जीपीएस ट्रैकिंग को लागू किया गया है और काम की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस के उन बिचौलियों को परेशानी हो रही है जो जल्दी पैसा कमा रहे थे इसीलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं।

उनका कहना है कि कांग्रेस ने एमएनआरईजीए में कांग्रेस शासनकाल के दौरान 11 लाख करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के आरोपों का विरोध नहीं किया। सीएजी की साल 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 43 लाख फर्जी जॉब कार्ड थे। पहले इनसे जेसीबी मशीनों से काम करवाया जाता था। जोशी ने स्पष्ट किया कि इन सभी अनियमितताओं और खामियों को उजागर करने के लिए 'वीबीजी रामजी अधिनियम' लाया गया है।

ममता बनर्जी सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री : तापस राय

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल सरकार में पूर्व मंत्री रहे तापस राय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2026 में बंगाल की जनता हर हाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है।

तापस राय ने ममता बनर्जी को 'देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री' करार देते हुए कहा कि मैं उनके (ममता बनर्जी) मंत्रिमंडल में सहयोगी रहा हूं और पार्टी के पुराने दौर में उनके साथ काम किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वह किस तरह नाटक, झूठ और नफरत की राजनीति करती हैं। हिंदू धर्म से नफरत करती हैं ममता : तापस रायतापस राय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदू धर्म और हिंदुओं से नफरत करती हैं, इसी कारण वह अल्पसंख्यक सम्मेलनों में जाकर हिंदू धर्म का अपमान करती हैं।

उन्होंने हाल ही में गंगासागर में सेतु के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कृष्ण परमहंस द्वारा गीता लिखे जाने के दावे को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आजकल हिंदुओं को लुभाने के लिए हिंदुत्व की बातें करने लगी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका हिंदू धर्म से कभी कोई संबंध नहीं रहा। न उन्हें धर्म का ज्ञान है, न इतिहास की समझ। वह रामकृष्ण परमहंस और भगवान श्रीकृष्ण के अंतर तक को नहीं समझतीं और किसी भी मंच से कुछ भी बोल देती हैं। मजहब के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर सत्ता में बनी रहीं तापस राय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हर धर्म के लोगों को गुमराह कर सत्ता में बने रहने की राजनीति करती हैं।

राय ने कहा कि उन्हें न इतिहास की समझ है, न धर्म की। वह केवल सत्ता बचाने की राजनीति जानती हैं। भतीजे के लिए तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं को किनारे लगायातापस राय ने तृणमूल कांग्रेस पर खुले तौर पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी की स्थापना से लेकर सत्ता में वापसी तक जिन नेताओं ने तन-मन-धन से योगदान दिया, उन्हें दरकिनार कर दिया गया और भतीजे अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी बना दिया गया।

उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी केवल अपना और अपने परिवार का भला सोचती हैं। तृणमूल के पुराने नेता इस अपमान को कैसे सहन कर रहे हैं, यह मेरी समझ से परे है। यह पूरी तरह राजनीतिक सुविधा के खिलाफ है। बंगाल की जनता त्रस्त, बदलाव तय तापस राय ने दावा किया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के शासन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और 2026 में बदलाव तय है। तापस ने कहा कि इस बार जनता हर हाल में परिवर्तन चाहती है और ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। नई जिम्मेदारी पर बोले तापस रायभाजपा में नई जिम्मेदारी मिलने पर तापस राय ने पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया।

नेपाल में चुनाव कराने को लेकर भारत-नेपाल के अफसरों की बैठक

लखीमपुर खीरी। नेपाल में आगामी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2026 के चुनाव को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को भारत-नेपाल समन्वय समिति की बैठक नेपाल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। बैठक में दोनों देशों ने चुनाव के दौरान सूचना आदान-प्रदान और सहयोग को सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत की ओर से लखीमपुर खीरी और नेपाल की ओर से कैलाली एवं कंचनपुर अंचल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि चुनाव के दौरान पूर्ण सहयोग और साझा सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। चुनाव कराने में आसानी होगी। हमारे संबंध अच्छे थे और भविष्य में भी बेहतर रहेंगे।

भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक बंधनों से जुड़े हैं। वहीं, भारत में लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने नेपाल के अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़ा है। उन्होंने इसे "रोटी-बेटी का रिश्ता" बताते हुए दोनों देशों के अटूट बंधन पर जोर दिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करना है। उन्होंने भरोसा जताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और एसएसबी नेपाल के अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। डीएम ने कहा कि इस संवाद से सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण और मजबूत होंगे और सीमावर्ती जनता को सुरक्षित और सहयोगपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि, सूचना का रियल टाइम आदान-प्रदान, और आपात सेवाओं की निर्बाध आवाजाही प्राथमिकताएं रहेंगी। एएसपी पवन गौतम ने कहा कि भारत की ओर से पेट्रोलिंग सतत जारी है। हम नेपाल की ओर से मिलने वाली सूचनाओं पर क्विक रेस्पॉन्ड करेंगे।

भारतीय अधिकारी रहे मौजूद

डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पवन गौतम, एसडीएम डॉ अवनीश, राजीव निगम, कमांडेंट 39 बटालियन आरके राजेश्वरी, डिप्टी कमांडेंट ऑपरेशन विजेंद्र कुमार सिंह, कमांडेंट 49 बटालियन शेर सिंह चौधरी, सेकेंड इन कमांडेंट थर्ड बटालियन एम डी तमांग, कमांडेंट 70 बटालियन राजन श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह मौजूद रहे।

नेपाल के ये अधिकारी रहे मौजूद

मुख्य जिलाधिकारी (कैलाली) हीरालाल रेग्मी, मुख्य जिलाधिकारी (कंचनपुर) मदन कोइराला असिस्टेंट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कैलाली किरण जोशी, असिस्टेंट चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, कंचनपुर मोहन चंद्र जोशी, एसपी कैलाली नरेंद्र चंद, एसपी कंचनपुर खड़ग बहादुर खत्री, एसपी एपीएफ कैलाली लोकेंद्र देव भट्ट, एसपी एपीएफ कंचनपुर सुरेंद्र राज रंजीत, डिप्टी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर महेश बोहरा, प्रकाश शाह, चीफ एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तारा नाथ पनेरू, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कैलाली शिव राज जोशी, सेक्शन ऑफिसर, कैलाली कल्पना भट्ट।

महिला के मौत बाद खड़गपुर में तनाव, आरोप पुलिस पर

खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर में पुलिस की कथित कार्रवाई के दौरान एक वृद्ध महिला की मौत को लेकर गुरुवार को जनआक्रोश चरम पर पहुंच गया। मृतका के परिजनों ने पुलिस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह से ही खड़गपुर-केशियाड़ी राज्य मार्ग पथावरोध कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवाद की जड़ खड़गपुर टाउन थाना अंतर्गत छोटा टेंगरा की ओड़िया बस्ती में एक निर्माणाधीन मकान की छत ढलाई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा है। पहले हिजली चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद रात करीब 10 बजे अनुमंडल पुलिस अधिकारी धीरज ठाकुर (एसडीपीओ) के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने इलाके में अभियान चलाया।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रदेश अधिवेशन 9 व 10 जनवरी को

अलवर। शहर में 36 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शिक्षा जगत से जुड़ा एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान के तत्वावधान में 64वां प्रदेश अधिवेशन 9 व 10 जनवरी को अलवर के मोटल रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा।

गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में संगठन के अध्यक्ष प्रो. मनोज बहरवाल और प्रदेश महामंत्री रिछपाल सिंह ने बताया कि यह अधिवेशन उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों का एक बड़ा विचार–विमर्श महासम्मेलन होगा। इसमें देश और प्रदेश के शिक्षा विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, शोधकर्ता एवं नीति निर्धारक भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचार, शोध, रोजगारोन्मुखी शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्यापक मंथन करना है। आयोजकों के अनुसार 36 वर्षों में पहली बार अलवर में इस स्तर का शिक्षा केंद्रित आयोजन हो रहा है, जो जिले के लिए गौरव का विषय है। आयोजकों ने कहा कि इस महासम्मेलन से अलवर को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और युवाओं, छात्रों व शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों से सीधे संवाद का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति, तकनीकी शिक्षा, शोध एवं नवाचार, मूल्य आधारित शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी।

सह संगठन मंत्री डॉ. गंगाश्याम गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष कर्मवीर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. लता शर्मा, प्रदेश मंत्री आंचल मीणा, विभाग संयोजक अजय वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि तथा वन मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सत्र की अध्यक्षता प्रो. नारायण लाल गुप्ता (महामंत्री) करेंगे। दूसरे दिन 10 जनवरी को शैक्षिक संगोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न विषयों पर पत्रवाचन और वैचारिक विमर्श किया जाएगा। संगोष्ठी के विषय प्रवर्तक प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरु कोटा विश्वविद्यालय होंगे, जबकि अध्यक्षता प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, कुलगुरु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर करेंगे।

समापन सत्र के मुख्य वक्ता निंबाराम, क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होंगे तथा अध्यक्षता महेंद्र कपूर, संगठन मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ करेंगे।

कड़ाके की ठंड व शीतलहर का प्रकोप जारी, स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने की मांग

जम्मू। शिवसेना (यू बीटी) जम्मू-कश्मीर ईकाई ने कड़ाके की ठंड व शीतलहर के जारी रहने पर स्कूलों की छुट्टियां को एक सप्ताह के लिए बढाने की मांग है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीश साहनी ने कहा कि कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। लगातार गिरते तापमान और सुबह के समय घने कोहरे के कारण बच्चों को स्कूल आने-जाने में स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड सकता है। साहनी ने कहा कि 13 , 14 जनवरी को लोहड़ी व मकर संक्रांति का पर्व है।

भोपाल के 2 लाख 49 हजार 467 विद्युत उपभोक्ताओं को दिसंबर में एक करोड़ 53 लाख की मिली छूट

स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिला सोलर ऑवर में 20 प्रतिशत छूट का लाभ

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 4 लाख 29 हजार 935 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके मासिक विद्युत बिल में टाइम ऑफ डे (ToD) छूट का लाभ प्रदान करते हुए दिसंबर 2025 में कुल 2 करोड़ 71 लाख 72 हजार की रियायत प्रदान की गई है।

इसमें भोपाल शहर के 2 लाख 49 हजार 467 उपभोक्ताओं को एक करोड़ 53 लाख 47 हजार रुपये की दिन के टैरिफ में छूट मिली है। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी खपत के आधार पर टाइम ऑफ डे (ToD) छूट के तहत यह रियायत दी गई है। जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने गुरुवार को बताया कि दिन के टैरिफ में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी (यदि कोई हो) को छोड़कर की जा रही है। कंपनी ने बताया है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जिसमें घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य और स्ट्रीट लाइट और निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सोलर ऑवर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की अवधि के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर पर 20 प्रतिशत की छूट 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को ही दी जा रही है। कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिसर में स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करें और स्मार्ट मीटर लगवाने से न घबराएं।

स्मार्ट मीटर उनके लिए हर तरह से फायदेमंद है और स्मार्ट मीटर की सटीक रीडिंग और बिलिंग के साथ ही कार्यप्रणाली में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट मीटर से बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा की खपत को ट्रैक करने और ऊर्जा की बचत करने में मदद मिलती है। स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को सटीक रूप से मापता है, जिससे बिल में कोई गलती नहीं होती। एप के जरिए मोबाइल पर रियल-टाइम डेटा देखकर ऊर्जा की खपत को नियंत्रित किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को ऊर्जा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ऊर्जा की खपत को बेहतर बनाया जा सकता है। उपभोक्ता ऊर्जा की खपत को ऑनलाइन मोबाइल एप के द्वारा किसी भी समय कहीं से भी देख सकते हैं। स्मार्ट मीटर ऊर्जा की खपत को कम करने में सहायक होकर पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम करता है।

वुलर झील का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मंत्री जावेद राणा

श्रीनगर। जल शक्ति, वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने दोहराया कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वुलर झील का संरक्षण और संवर्धन बनी हुई है।

सिविल सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे झील के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और इसके संसाधनों के सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपाय तैयार करें और उन्हें लागू करें। बैठक में वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण आयुक्त सचिव शीतल नंदा, कश्मीर के मुख्य वन संरक्षक इरफान रसूल वानी, डब्ल्यूयूसीएमए के सीईओ मंजूर कादरी, पीडब्ल्यूडी कश्मीर के मुख्य अभियंता नरिंदर कुमार, अधीक्षण अभियंता और संबंधित मंडल वन अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री ने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जल निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि वुलर झील जल शुद्धिकरण, बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्होंने झील के दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। झील के आसपास सौंदर्यीकरण और भूदृश्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, राणा ने समय पर निविदा जारी करने और क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं

सबकी समस्या का निराकरण सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार का संकल्प है। सीएम ने अफसरों को निर्देशित किया कि वे पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले।

हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। कुर्सियों पर बैठे लोगों तक खुद गए। उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए

त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ति की समस्या का समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए कई लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए।

सीएम योगी ने की गोसेवा गोवंश को खिलाया गुड़

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की। गायों और गोवंश को स्नेहिल भाव से गुड़ खिलाया। गुरुवार सुबह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिजनों के साथ आए बच्चों से मिल उन्हें प्यार-दुलार, आशीर्वाद और चॉकलेट दिया।

समाजवादी पार्टी के दुद्धी से विधायक विजय सिंह गोंड का निधन

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक तथा वरिष्ठ आदिवासी नेता विजय सिंह गोंड का बृहस्पतिवार को लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 71 साल के थे । परिवार के सूत्रों ने यह जानकारी दी समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक के निधन की पुष्टि सपा नेता अवध नारायण यादव ने की। उप्र से आठ बार विधायक रहे गोंड लंबे समय से बीमार थे, और लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में उपचाराधीन थे । सपा विधायक की दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था ।

यादव ने कहा कि विजय सिंह गोंड लंबे समय से बीमार थे और लखनऊ में उपचाराधीन थे। उनका निधन क्षेत्र और आदिवासी समुदाय के लिए एक अपूरणीय क्षति है। गोंड 2024 के उपचुनाव में दुद्धी से सपा उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। यह उपचुनाव तब जरूरी हुआ जब तत्कालीन विधायक रामदुलार गोंड को एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 1980 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए, गोंड पहली बार दुद्धी से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उन्होंने 1985 में कांग्रेस टिकट पर, 1989 में निर्दलीय के रूप में, और बाद में 1991 और 1993 में जनता दल के विधायक के तौर पर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्होंने 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान, उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा था। अपने लंबे राजनीतिक करियर के बावजूद, गोंड को भाजपा की मजबूत चुनावी लहर के बीच 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। जिला और राज्य दोनों स्तरों पर एक प्रमुख आदिवासी नेता के रूप में व्यापक रूप से माने जाने वाले गोंड आदिवासी समुदायों के कल्याण और अधिकारों से संबंधित मुद्दों को लगातार उठाने के लिए जाने जाते थे।

उन्हें क्षेत्र के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव वाले जमीनी नेता के रूप में भी देखा जाता था। यादव ने कहा कि गोंड का पार्थिव शरीर बृहस्पतिवार शाम तक दुद्धी पहुंचने की उम्मीद है और अंतिम संस्कार दुद्धी में कंधार नदी के किनारे किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गोंड के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

बलिया में HIV मरीजों की संख्या पहुंची 3126

बलिया। जनपद में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3126 हो गयी है। सबसे भयावह यह कि इसमें निरन्तर वृद्धि जारी है। एचआईवी मरीजो में वृद्धि की सबसे बड़ी वजह ट्रांस जेंडर बताए जा रहे हैं। हालांकि एक ही सीरिंज से बार-बार इजेक्शन देने से भी एड्स के फैलने की संभावना बनी रहती है। वहीं, बिना जांच के ब्लड चढ़ाने और असुरक्षित यौन न सम्बंध बनाने से भी एड्स फैलता है। जनपद में इस वक्त 3126 एचआईवी पॉजिटिव हैं। प्रभारी सीएमओ डाक्टर विजय कुमार यादव ने बताया कि जनपद में 1601 पुरुष, 1323 महिला, 113 बच्चे और 64 बच्चियां व 22 ट्रांस जेंडर शामिल हैं। जिनका इलाज चल रहा है। एसीएमओ डा. विजय कुमार यादव ने कहा कि जिले में एचआईवी के फैलने में ट्रांस जेंडर की भूमिका अहम है। समय-समय पर उन्हें असुरक्षित सेक्स से बचने की सलाह दी जाती है।

सपा खुद पीडीए को लेकर भ्रम में है: पंकज चौधरी

वाराणसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के हाल में जारी 'पीडीए पंचांग' पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी खुद ही इस बात को लेकर पक्का नहीं है कि पीडीए का मतलब क्या है, जबकि भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली समावेशी राजनीति में विश्वास करती है।

हाल में समाजवादी पार्टी ने 2026 के लिए अपना 'समाजवादी पीडीए पंचांग' जारी किया है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा जारी किए गए इस कैलेंडर में प्रमुख राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तारीखों के साथ-साथ पार्टी के विचारकों, संस्थापकों और पीडीए - पिछड़ा (पिछड़ी जातियां), दलित और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सामाजिक हस्तियों की जयंती एवं

पुण्यतिथि को भी दिखाया गया है। यह पंचांग सपा की राजनीतिक पहुंच के हिस्से के रूप में देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बांटा जा रहा है।

चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में प्रेसवार्ता में कहा कि भाजपा किसी एक जाति की पार्टी नहीं बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी को यह तय करना चाहिए कि पीडीए का असल में मतलब क्या है। सपा खुद पीडीए को लेकर कन्फ्यूजन में है, जबकि भाजपा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर काम करती है।

चौधरी बुधवार रात वाराणसी पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है और इसे समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है, न कि सरकार द्वारा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि चुनाव से जुड़ा काम जमीनी स्तर तक पहुंचे। आगामी बजट पर चौधरी ने कहा कि यह एक बार फिर आम लोगों को समर्पित होगा, जिसमें गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी चुनावी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। ब्राह्मण विधायकों की बैठकों समेत समुदाय-विशिष्ट पहुंच से जुड़े सवालों पर, उन्होंने दोहराया कि भाजपा समाज के हर वर्ग को शामिल करके विकास-उन्मुख राजनीति करती है।

संभल मंदिर-मस्जिद विवाद : अदालत में 24 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई

संभल। उत्तर प्रदेश के चंदौसी की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शाही जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की। यह मुकदमा दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।

शाही जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद वारसी ने पत्रकारों से कहा कि इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी थी लेकिन उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश होने के कारण सुनवाई टाल दी गई और अब अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई की वैधता को चुनौती दी थी लेकिन पिछले साल 19 मई को अदालत ने

अधीनस्थ न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की इजाजत दी गई थी और मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि चूंकि इस मामले में उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी। यह विवाद पिछले साल 19 नवंबर को उस समय हुआ था, जब वकील हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर कर दावा किया था कि मस्जिद एक पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। उसी दिन (19 नवंबर) अदालत के आदेश पर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसके बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण किया गया। दूसरे सर्वे के कारण संभल में हिंसा भड़क गयी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क व मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली के साथ-साथ 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

ट्रक ने बाइकसवारों को मारी टक्कर, पिता और दो बेटों की मौत

बरेली। कोतवाली बहेड़ी क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और उसके दो बेटों की मौत हो गई। तीन मजदूर थे और सुबह मजदूरी करने जा रहे थे। दुर्घटना में पिता और दो बेटों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

थाना देवरनियां क्षेत्र के गांव इटौआ निवासी 55 वर्षीय पप्पू गुरुवार सुबह करीब आठ बजे अपने दो बेटों 20 वर्षीय विवेक कुमार और 15 वर्षीय विशाल कुमार के साथ बाइक से मजदूरी करने किच्छा जा रहे थे। जैसे ही वे गुड़वारा गांव के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

पुलिस ने मृतकों की जेब में मिले कागजातों के आधार पर परिजनों को सूचना दी। मृतक की चाची सरोज देवी ने बताया कि पप्पू छह बच्चों का पिता था और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। पत्नी शीला का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह घना कोहरा होने के कारण हादसा हुआ। इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर फरार चालक की तलाश की जा रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम अमेठी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल, नेतृत्व ने दिया बड़ा संकेत

अमेठी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का नाम अमेठी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज है। इस कदम को अमेठी से उनके राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से यह चर्चा थी कि स्मृति ईरानी अमेठी से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है।

माना जा रहा है कि इससे पार्टी नेतृत्व का संकेत है कि स्मृति ईरानी की सक्रियता अमेठी में बनी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में स्मृति ईरानी का नाम गौरीगंज तहसील क्षेत्र की मेदन मवई ग्राम पंचायत में शामिल है। वह कम्पोजिट विद्यालय लीला टिकरा, मेदन मवई स्थित मतदान केंद्र की

नाम क्रमांक 514 पर अंकित है। स्मृति ईरानी ने वर्ष 2021 में मेदन मवई गांव में 11 बिस्वा भूमि खरीदी थी। 22 फरवरी 2021 को भूमि की रजिस्ट्री कराई गई, जबकि 29 जुलाई 2021 को मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। इस बूथ पर कुल 666 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें स्मृति ईरानी का उनके पुत्र जोहर ईरानी ने भूमि पूजन कर आवास निर्माण की आधारशिला रखी थी। निर्माण पूर्ण होने के बाद 22 फरवरी 2024 को स्मृति ईरानी ने गृह प्रवेश किया। तभी से उनका अमेठी में नियमित आना-जाना बना हुआ है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल होना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संकेत भी हैं। स्मृति ईरानी ने वर्ष 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराकर अमेठी लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद अमेठी से उनका रिश्ता समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच भाजपा के अमेठी जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने बृहस्पतिवार को बताया कि कि स्मृति ईरानी अमेठी की स्थायी निवासी हैं और उनका स्नेह हमेशा कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रहा है।

मरीजों को बेहतर इलाज देना सरकार की प्राथमिकता : डिप्टी सीएम पाठक

बरेली। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के गुरुवार को बरेली पहुंचने पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और राजनीतिक हलकों में हलचल देखने को मिली। दोपहर करीब डेढ़ बजे एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने सीधे इज्जतनगर क्षेत्र के पीरबहोड़ा स्थित अर्बन

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रुख किया। यहां उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण काउंटर और जांच कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया।

मरीजों से संवाद कर इलाज और सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानी। निरीक्षण के दौरान कुछ व्यवस्थाओं में कमी मिलने पर उप मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिलना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री पीलीभीत बाईपास रोड स्थित शक्तिनगर कॉलोनी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत विधायक को सादगी और जनसेवा का प्रतीक बताते हुए उनके निधन को क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उप मुख्यमंत्री ने विधायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

तौकीर रजा के बेटे के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज

शाहजहांपुर। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के एक नेता के बेटे के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसने कथित तौर पर अपनी कार से एक बस में टक्कर मार दी थी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फरमान रजा खान (30) के खिलाफ यह दूसरी प्राथमिकी है, जिस पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद उसकी कार से कुछ 'क्रिस्टल मेथ' मिली थी, जो एक गैर-कानूनी मादक पदार्थ है ।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को बताया कि मंगलवार देर रात बरेली निवासी तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा खान (30) अपनी कार से बरेली की ओर जा रहे थे, इनकी कार थाना तिलहर अंतर्गत कछियानी खेड़ा मंदिर के पास पहुंची तभी आगे चल रही रोडवेज बस में इनकी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, परंतु कार की पुलिस द्वारा तलाशी लेने के दौरान एक बैग में रखा आधा ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ था। उन्होंने बताया कि इसी मामले में बुधवार शाम को सीतापुर डिपो के बस चालक शिवेंद्र पांडे ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि उनकी बस हरिद्वार जा रही थी मंदिर के पास भीड़भाड़ होने के चलते वह अपनी बस को धीमी गति से चला रहा था तभी पीछे से आई कार ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बस का काफी नुकसान हुआ है।

इसमें कहा गया है कि कार फरमान चला रहा था। द्विवेदी ने बताया कि इस मामले में थाना पुलिस ने आरोपी कार चालक फरमान रजा खान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) 324 (4) (संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पिछले वर्ष बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्ट से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में खान को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद से तौकीर रजा जेल में है। इससे पहले, फरमान को स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था ।

ट्रक ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, दो मजदूरों की मौत

बरेली। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के बीच बरेली-पीलीभीत राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके कारण दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (उत्तर) मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि यह हादसा बृहस्पतिवार सुबह हाफिजगंज थाना क्षेत्र में राजश्री कॉलेज के पास हुआ, जब पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। ई-रिक्शा में सवार मजदूरों की पहचान सलीम (35) और हाशिम (35) के रूप में हुई है, दोनों नवाबगंज थाना क्षेत्र के रिचोला किफायतुल्ला गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि टक्कर के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में ई-रिक्शा में सवार दो अन्य लोग - नसरुद्दीन (36) और रईस अहमद उर्फ मजले (34) गंभीर रूप से घायल हो गए। मिश्रा ने बताया कि चारों दिहाड़ी मजदूरी के लिए रिठोरा जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ट्रक को कब्जे में लेकर उसके फरार चालक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस इस दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रही है।

प्रदेश सरकार आयुष्मान अस्पतालों को 30 दिन में कर रही भुगतान, मरीजों के इलाज के लिये दिये 4,649 करोड़

लखनऊ। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज कराने वाले परिवारों के लिए जहां कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया है, वहीं योजना से जुड़े अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर व्यवस्था को और मजबूत किया है। इसी का नतीजा है कि पिछले एक वर्ष में आयुष्मान योजना के क्लेम निस्तारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जनवरी-25 में जहां क्लेम की पेंडेंसी 10 लाख 75 हजार तक पहुंच गई थी, वहीं दिसंबर-25 तक यह घटकर मात्र 3 लाख रह गयी है। स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज(साचीज) की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत क्लेम के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जनवरी-25 में

जहां क्लेम की पेंडेंसी 10 लाख 75 हजार तक पहुंच गई थी, वहीं दिसंबर 2025 तक यह घटकर मात्र 3 लाख रह गयी है। इसे भी जल्द ही निस्तारित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योजना के तहत प्रति माह औसतन 2 लाख से अधिक क्लेम अस्पतालों से प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले क्लेम का समयबद्ध निस्तारण एक बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुराने लंबित मामलों के साथ-साथ नए क्लेम का भी नियमित और सुव्यवस्थित तरीके से निस्तारण हो।

साचीज की एसीईओ पूजा यादव ने बताया कि मेडिकल ऑडिटरों की संख्या 40 से बढ़ाकर 130 कर दी गई है। इससे क्लेम की जांच प्रक्रिया तेज हुई है। इसके साथ ही क्लेम प्रोसेसिंग डेस्क (CPD) की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। योजना के तहत अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स का भुगतान 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा यानी टर्न अराउंड टाइम (TAT) के भीतर किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एजेंसी स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और लंबित मामलों की सतत निगरानी की जा रही है। साचीज की सीईओ ने बताया कि जनवरी-25 से दिसंबर-25 की अवधि के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों को क्लेम्स के सापेक्ष कुल 4,649 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

आंकड़ा दर्शाता है कि योगी सरकार न सिर्फ इलाज की व्यवस्था कर रही है, बल्कि अस्पतालों के आर्थिक हितों की भी पूरी तरह से रक्षा कर रही है, ताकि वे गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। योगी सरकार की नीतियों से क्लेम पेंडेंसी में कमी, समयबद्ध भुगतान और मजबूत ऑडिट व्यवस्था ने अस्पतालों का विश्वास बढ़ाया है। इसका सीधा लाभ गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मिल रहा है ।

ऑस्ट्रेलिया ने पांचवां टेस्ट पांच विकेट से जीतकर एशेज 4-1 से अपने नाम की

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में रोमांचक जीत के साथ उस्मान ख्वाजा को दी विदाई

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को पांच विकेट से हराकर एशेज सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। यह मुकाबला पूरे सीरीज का सबसे करीबी टेस्ट साबित हुआ, जिसमें पांचवें दिन की घूमती पिच, अंपायरिंग तकनीक को लेकर विवाद और आखिरी क्षणों का दबाव – सब कुछ देखने को मिला। इंग्लैंड की तीसरी पारी में जैकब बेथेल के शानदार 154 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ाई और 39 रन बाकी रहते उसका पांचवां विकेट गिर गया। इसके बाद एलेक्स कैरी (नाबाद 16) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 22) ने छठे विकेट के लिए नाजुक लेकिन निर्णायक 40 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई। कैरी ने विल जैक्स की गेंद पर विजयी रन लगाए।

इंग्लैंड की ओर से जोश टंग ने 11 ओवर में 3/42 की जुझारू गेंदबाजी की, लेकिन अनुभवी स्पिनर की कमी इंग्लैंड को भारी पड़ी, क्योंकि पिच पर तेज टर्न मिलने लगा था। कप्तान बेन स्टोक्स ग्रोइन इंजरी के बावजूद टीम का नेतृत्व करते नजर आए और डीआरएस से जुड़े एक और फैसले को लेकर वह खासे नाराज दिखे। इस टेस्ट का एक भावुक पल उस समय आया जब उस्मान ख्वाजा अपने आखिरी टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करने उतरे। बेन स्टोक्स ने खेल भावना दिखाते हुए उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर का आयोजन किया। ख्वाजा सिर्फ 6 रन ही बना सके और जोश टंग की गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट होने के बाद उन्होंने मार्नस लाबुशेन से गले लगकर विदाई ली, परिवार की ओर हाथ हिलाया और मैदान पर लिखे 'थैंक्स उज्जी' संदेश को नमन किया।

मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन जल्दी आउट हुए, लेकिन इंग्लैंड के पार्ट-टाइम स्पिनर मैच का रुख नहीं बदल सके। इस बीच जेक वेदराल्ड और ब्रायडन कार्स के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसकी वजह डीआरएस से जुड़ा विवाद रहा। इस टेस्ट में बेथेल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया, जबकि पूरे सीरीज में 31 विकेट और 156 रन बनाने वाले मिशेल स्टार्क को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार मिला।

इस हार के साथ इंग्लैंड की विदेशी धरती पर खराब फॉर्म जारी रही है। टीम ने अपने पिछले 17 विदेशी टेस्ट में सिर्फ पांच जीते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू मैदान पर अपना दबदबा कायम रखते हुए एक और यादगार एशेज सीरीज अपने नाम कर ली।

डब्ल्यूटीसी 2025-27 पॉइंट्स टेबल अपडेट: एशेज के बाद ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर मजबूत, इंग्लैंड 7वें स्थान पर

नई दिल्ली। एशेज सीरीज के समापन के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 की अंक तालिका अपडेट हो गई है। पांच मैचों की एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हराकर शीर्ष स्थान पर अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है, जबकि इंग्लैंड की टीम अंक तालिका में सातवें पायदान पर संघर्ष करती नजर आ रही है। सिडनी में खेले गए पांचवें और आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पांच विकेट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक खेले गए 8 मैचों में 7 जीत दर्ज की हैं, जबकि उसकी इकलौती हार बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ आई थी। दूसरी ओर, इंग्लैंड का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीम ने 10 मैचों में सिर्फ 3 जीत हासिल की हैं, जबकि उसे 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। स्लो ओवर-रेट के चलते इंग्लैंड के दो अंक भी काटे गए हैं।

आईसीसी डब्ल्यूटीसी 2025-27 अंक तालिका

1. **ऑस्ट्रेलिया** – मैचः 8, जीतः 7, हारः 1, ड्रॉः 0, अंकः 84, अंक प्रतिशतः 87.50
2. **न्यूजीलैंड** – मैचः 3, जीतः 2, हारः 0, ड्रॉः 1, अंकः 28, अंक प्रतिशतः 77.78
3. **दक्षिण अफ्रीका-** मैचः 4, जीतः 3, हारः 1, ड्रॉः 0, अंकः 36, अंक प्रतिशतः 75.00
4. **श्रीलंका** – मैचः 2, जीतः 1, हारः 0, ड्रॉः 1, अंकः 16, अंक प्रतिशतः 66.67
5. **पाकिस्तान** – मैचः 2, जीतः 1, हारः 1, ड्रॉः 0, अंकः 12, अंक प्रतिशतः 50.00
6. **भारत** – मैचः 9, जीतः 4, हारः 4, ड्रॉः 1, अंकः 52, अंक प्रतिशतः 48.12
7. **इंग्लैंड*** – मैचः 10, जीतः 3, हारः 6, ड्रॉः 1, अंकः 38, अंक प्रतिशतः 31.67
8. **बांग्लादेश** – मैचः 2, जीतः 0, हारः 1, ड्रॉः 1, अंकः 4, अंक प्रतिशतः 16.67
9. **वेस्टइंडीज** – मैचः 8, जीतः 0, हारः 7, ड्रॉः 1, अंकः 4, अंक प्रतिशतः 4.17

पीवी सिंधू आसान जीत के साथ मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में

कुआलालंपुर। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार को यहां अपने से अधिक रैंकिंग वाली जापान की खिलाड़ी तोमोका मियाजाकी को हराकर मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की।

चोट के कारण लंबे समय तक खेल से दूर रहने के बाद वापसी कर रही पूर्व विश्व चैंपियन सिंधू ने आठवीं वरीयता प्राप्त मियाजाकी को 33 मिनट में 21-8, 21-13 से हराया। हालांकि भारतीय पुरुष खिलाड़ी लक्ष्य सेन और युवा आयुष शेट्टी को हार का सामना करना पड़ा। सेन प्री-क्वार्टर फाइनल में हांगकांग-चीन के ली चेउक यिउ से 53 मिनट में 22-22, 15-21 से हार गए। शेट्टी को चीन के शीर्ष वरीयता प्राप्त शी यू क्यूई के खिलाफ 70 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 18-21, 21-18, 12-12 से हार का सामना करना पड़ा। तीस वर्षीय सिंधू ने वापसी करने के बाद अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और मियाजाकी के खिलाफ अपनी दूसरी जीत दर्ज की। इससे जापानी किशोरी के खिलाफ उनका करियर का रिकॉर्ड 2-1 हो गया है।

सिंधू ने पहले गेम में 5-1 की बढ़त हासिल की और फिर लगातार 13 अंक जीतकर 18-4 की शानदार बढ़त बना ली। इसके बाद उन्होंने पहला गेम आसानी से अपने नाम कर लिया। दूसरा गेम भी काफी हद तक एकतरफा रहा, हालांकि 19 वर्षीय मियाजाकी 8-9 से पिछड़ने के बाद कुछ समय के लिए मुकाबले में बनी रहीं। लेकिन सिंधू ने अपने अनुभव का अच्छा इस्तेमाल किया और 17-11 से छह अंक की बढ़त बना ली। इसके बाद उन्हें मैच जीतने में ज्यादा समय नहीं लगा। क्वार्टर फाइनल में सिंधू का सामना चीन की गाओ फांग जी और तीसरी वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी अकाने यामागुची के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

क्रिकेटर राजन कुमार डोप टेस्ट में विफल, फर्राटा धाविका धनलक्ष्मी पर आठ साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली। क्रिकेट से जुड़े एक दुर्लभ मामले में उत्तराखंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राजन कुमार के डोप जांच में पॉजिटिव पाये जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस 29 साल के क्रिकेटर के नमूने में 'एनाबॉलिक स्टेरॉयड' ड्रोस्टानोलोन और मेटेनोलोन के साथ-साथ क्लोमीफीन भी पाया गया, जिसका उपयोग आमतौर पर महिलाओं में बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है।

यह हालांकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। उत्तराखंड के इस खिलाड़ी ने अपना पिछला मैच आठ दिसंबर को अहमदाबाद में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप डी के मैच में दिल्ली के खिलाफ खेला था। क्रिकेटरों के डोप जांच में विफल होने के मामले बहुत कम हैं। मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर अंशुला राव 2020 में डोपिंग के लिए पकड़े गए थे, जबकि पृथ्वी साव 2019 में डोप जांच में पॉजिटिव पाये गये थे।

नोंगमैथेम रतनबाला देवी भी डोप टेस्ट में विफल होने वाली दुर्लभ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गईं। उनका नाम भी अस्थायी निलंबन पाने वाले खिलाड़ियों की नवीनतम सूची में शामिल है। उनके नमूने में एनाबॉलिक स्टेरॉयड मेटांडिएनोन पाया गया था। इस सूची में अन्य खिलाड़ी गौरव पटेल (एथलेटिक्स), खुशबू कुमारी (भारोत्तोलन), अचलवीर करवासरा (मुक्केबाजी और सिद्धांत शर्मा (पोलो) हैं।

तमिलनाडु की फर्राटा धाविका धनलक्ष्मी शेखर पिछले साल अपने करियर में दूसरी बार डोप जांच में पॉजिटिव पायी गयी थी। उन पर नौ सितंबर 2025 से आठ साल का प्रतिबंध लगाया गया है। सितंबर 2025 में उनके नमूने में एनाबॉलिक स्टेरॉयड ड्रोस्टानोलोन की पुष्टि हुई थी। यह उनका दूसरा डोप अपराध था। इस 27 साल की खिलाड़ी ने 2022 में डोप अपराध के लिए तीन साल का प्रतिबंध काटने के बाद 2025 में खेल में वापसी की थी।

यौन उत्पीड़न मामले में निशानेबाजी कोच निलंबित

नई दिल्ली। भारत के निशानेबाजी कोचिंग स्टाफ के एक प्रमुख सदस्य अंकुश भारद्वाज पर एक नाबालिग निशानेबाज ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके चलते राष्ट्रीय महासंघ ने उन्हें निलंबित कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने पुष्टि की है कि फरीदाबाद में भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एनआरएआई के सचिव राजीव भाटिया ने बताया कि एनआरएआई ने उन्हें निलंबित कर दिया है और हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे।" उन्होंने कहा कि उन्हें नैतिक आधार पर निलंबित किया गया है। अब उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना होगा। जांच पूरी होने तक वह किसी भी तरह की कोचिंग गतिविधि से नहीं जुड़े रहेंगे। भाटिया ने कहा कि एनआरएआई ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के बाद 37 सदस्यीय कोचिंग टीम में भारद्वाज को स्थान देने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि एनआरएआई की सिफारिश पर ही भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) ने उन्हें कोच नियुक्त किया था।

एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे तूर

नई दिल्ली। एशियाई खेलों में दो बार के स्वर्ण पदक विजेता गोला फेंक (शॉट-पुट) खिलाड़ी तजिंदरपाल सिंह तूर छह से आठ फरवरी तक चीन के तियानजिन में होने वाली 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। टीम इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए तीन फरवरी को रवाना होगी। भारतीय टीम में दो बार एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके तूर के अलावा युवा गोला फेंक खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल भी शामिल हैं।

तूर तियानजिन में स्वर्ण पदक जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक होंगे, क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से एशियाई इंडोर चैंपियनशिप में अपनी स्पर्धा में दबदबा बनाए हुए हैं। तूर ने 2024 में तेहरान में आयोजित 11वीं एशियाई इंडोर प्रतियोगिता में 19.72 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। पंजाब के 31 वर्षीय खिलाड़ी तूर ने अस्ताना में 2023 में महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भी शीर्ष स्थान हासिल किया था। उसी वर्ष उन्होंने भुवनेश्वर में 21.77 मीटर का राष्ट्रीय आउटडोर रिकॉर्ड बनाया था।

लंबी कूद के खिलाड़ी शाहनवाज खान और त्रिकूद में अनुभवी खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल भी नए सत्र की शानदार शुरुआत करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तेजस्विन शंकर (हेप्टाथलॉन) और मणिकांत होब्लिधर (60 मीटर) इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पुरुष टीम के अन्य प्रमुख खिलाड़ी हैं। देश की शीर्ष महिला फर्राटा धाविका नित्या गंधे और अभिनया राजाराजन 60 मीटर दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी, जबकि मौमिता मंडल महिलाओं की 60 मीटर बाधा दौड़ और लंबी कूद में भाग लेंगी।

भारतीय टीम इस प्रकार हैः पुरुषः मणिकांत होबलीधर (60 मीटर), तेजस शिरसे (60 मीटर बाधा दौड़), जे आदर्श राम (ऊंची कूद), सीवी अनुराग और शाहनवाज खान (लंबी कूद), प्रवीण चित्रवेल (त्रिकूद), समरदीप सिंह गिल, तजिंदरपाल सिंह तूर (शॉट पुट), तेजस्विन शंकर (हेप्टाथलॉन)।

महिलाः नित्या गंधे, अभिनया राजराजन (60 मीटर), मौमिता मंडल और प्रज्ञान प्रशांति साहू (60 मीटर बाधा दौड़), पूजा (ऊंची कूद), एंसी सोजन और मौमिता मंडल (लंबी कूद), योगिता (शॉट पुट) और केए अनामिका (पेंटाथलॉन)।

एयर इंडिया को निजीकरण के बाद मिला अपना पहला ड्रीमलाइनर विमान

नई दिल्ली। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने निजीकरण के बाद अपना पहला बोइंग 787-9 विमान प्राप्त कर लिया है। टाटा समूह ने जनवरी 2022 में सरकार से विमानन कंपनी का स्वामित्व हासिल किया था। यह एयर इंडिया के लिए विशेष रूप से विनिर्मित या 'लाइन फिट' पहला ड्रीमलाइनर विमान भी है। सामान्य तौर पर, 'लाइन फिट' का तात्पर्य किसी विशेष विमानन कंपनी के लिए विशेष रूप से विनिर्मित विमान से होता है।

एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि एयर इंडिया ने सात जनवरी को सिएटल में बोइंग के एवरेट कारखाने में 'ड्रीमलाइनर' का स्वामित्व हासिल किया। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निरीक्षण के बाद इस विमान के अगले कुछ दिन में भारत पहुंचने की उम्मीद है। जनवरी 2022 में निजीकरण के बाद एयर इंडिया द्वारा लिया जाने वाला यह पहला 'लाइन फिट' ड्रीमलाइनर है। नए विमान में तीन श्रेणियों इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास होंगी। एयर इंडिया ने आखिरी बार 'लाइन फिट' ड्रीमलाइनर अक्टूबर 2017 में हासिल किया था जब विमानन कंपनी सरकार के स्वामित्व में थी। अधिकारी ने बताया कि यह नवीनतम विमान उसका पहला 'वाइड-बॉडी' विमान है और 2023 में ऑर्डर किए गए 220 बोइंग विमान में से 52वां विमान है। एयर इंडिया एक्सप्रेस को पहले ही 'नैरो-बॉडी' बोइंग 737-8 के 51 विमान की आपूर्ति मिल चुकी है। इसमें दिसंबर के अंत में शामिल किया गया उसका पहला 'लाइन फिट' विमान भी शामिल है। टाटा समूह द्वारा जनवरी 2022 में अधिग्रहण के बाद, एयर इंडिया ने 350 एयरबस और 220 बोइंग विमान का ऑर्डर दिया।

एयरबस के ऑर्डर में से 6 ए350 विमान पहले ही एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं। एयर इंडिया के पास पहले से ही विस्तारा के 26 बी787-8 और 6 बी787-9 विमान हैं। विस्तारा का विलय एयर इंडिया में हो चुका है। एयर इंडिया समूह के पास वर्तमान में 300 से अधिक विमान हैं जिनमें से 185 विमान एयर इंडिया के हैं और शेष एयर इंडिया एक्सप्रेस के हैं। अधिकारी ने बताया कि पुराने करीब एक दर्जन ड्रीमलाइनर विमान नए रूप में 2026 तक सेवा में लौट सकते हैं।

झारखंड के मुख्यमंत्री दावोस बैठक में होंगे शामिल, ब्रिटेन भी जाएंगे

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कंपनी हरटेक पावर ने कर्नाटक में 353.77 करोड़ रुपये का नवीकरणीय ऊर्जा अनुबंध हासिल है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। कंपनी के बयान के अनुसार, उसे चल्लाकेरे में 80 मेगावाट / 320 एमब्ल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 280 मेगावाट एसी / 410 एमडब्ल्यूची डीसी सोलर पीवी परियोजना के लिए ईपीसी अनुबंध मिला है। हरटेक पावर ने कहा कि कार्य के दायरे में परियोजना की डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना और उसे चालू करना शामिल है। साथ ही एक वर्ष का संचालन और रखरखाव भी शामिल है। कंपनी ने बताया कि इस परियोजना के लिए जो काम तय किए गए हैं और जिन पर दोनों पक्षों ने सहमति दी है, उनका कुल अनुबंध मूल्य लगभग 353.77 करोड़ रुपये है।

उप्र की 'बिस्मिल' गन्ने की किस्म को चार अन्य राज्यों में खेती के लिए मिली मंजूरी

बरेली। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद ने स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर 'बिस्मिल' नामक गन्ने की एक नई उच्च उपज वाली किस्म विकसित की है, जिसे अब चार अन्य राज्यों में खेती के लिए मंजूरी मिल गई है। परिषद के निदेशक वी. के. शुक्ला ने बताया कि यह किस्म जिसे पहले केवल उत्तर प्रदेश के लिए मंजूरी मिली थी।

केंद्रीय समिति की हरी झंडी के बाद अब इसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी खेती के लिए भी मंजूरी मिल गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत विकसित इस किस्म को आधिकारिक तौर पर सीओएसएचए 17231 (कोयंबटूर-शाहजहांपुर) नाम दिया गया है। इस किस्म के 'ब्रीडर' डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि यह किस्म गन्ने की फसल के लिए एक बड़ा खतरा मानी जाने वाली लाल सड़न (रेड रॉट) से निपटने में सक्षम है। इसकी औसत पैदावार क्षमता 86.35 टन प्रति हेक्टेयर है जिसमें शर्करा प्राप्ति (गन्ने में पोल प्रतिशत) 13.97 प्रतिशत है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अजय तिवारी ने कहा कि यह नई किस्म किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी करेगी और साथ ही चीनी उत्पादन को भी बढ़ाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस किस्म का नाम क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के सम्मान में 'बिस्मिल' रखा गया है जिन्होंने काकोरी कांड में अहम भूमिका निभाई थी।

बिस्मिल को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। प्रसार अधिकारी संजीव पाठक ने कहा कि इस किस्म के बीज पहले ही उत्तर प्रदेश के सभी 42 गन्ना उगाने वाले जिलों में बांटे जा चुके हैं जिनके नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। उन्होंने कहा, '' चार अतिरिक्त राज्यों के लिए मंजूरी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

रुपया सात पैसे टूटकर 89.94 प्रति डॉलर पर बंद

मुंबई। रुपया बृहस्पतिवार को सात पैसे टूटकर 89.94 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, विदेशी पूंजी की निकासी और डॉलर के मजबूत रुख से घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिका के अधिक शुल्क लगाए जाने की आशंका और घरेलू शेयर बाजारों में कमजोर रुख ने स्थानीय मुद्रा पर और दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 89.96 प्रति डॉलर पर खुला।

कारोबार के दौरान 89.73 से 90.13 प्रति डॉलर के बीच इसने कारोबार किया। अंततः यह 89.94 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट है। रुपया बुधवार को 31 पैसे चढ़कर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.87 पर बंद हुआ था। फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, '' अगर अमेरिका शुल्क में 0.1 प्रतिशत की भी बढ़ोतरी करता है तो भारत को अपने निर्यात में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भावनात्मक रूप से स्थिति 'समझौते के करीब' होने से 'फिर से शुरुआत' करने जैसी हो जाएगी। वहीं बाजार में केंद्रीय बैंक की 'शॉर्ट सेलिंग' से डॉलर की खरीदारी का माहौल बना रहेगा।" उन्होंने कहा कि शुक्रवार को रुपये के 89.80 से 90.30 के बीच रहने का अनुमान है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 98.70 पर रहा।

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन टूटा, अमेरिकी शुल्क की चिंता से सेंसेक्स 780 अंक लुढ़का

मुंबई। वैश्विक बाजारों में व्यापक बिकवाली और अमेरिकी शुल्क बढ़ाए जाने की आशंका के बीच बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 780 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी को 264 अंकों का बड़ा नुकसान हुआ। विश्लेषकों के मुताबिक, धातु, तेल एवं गैस और जिंस शेयरों में भारी बिकवाली और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निरंतर निकासी ने बाजार पर दबाव बनाए रखा।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 780.18 अंक यानी 0.92 प्रतिशत लुढ़ककर 84,180.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 851.04 अंक तक गिरकर 84,110.10 के स्तर तक आ गया था। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 263.90 अंक यानी 1.01 प्रतिशत टूटकर 25,876.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से लार्सन एंड टुब्रो, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील और ट्रेंट सबसे ज्यादा नुकसान में रहीं। दूसरी तरफ, इटर्नल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऐसे प्रतिबंधात्मक विधेयक का समर्थन किए जाने से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है, जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा सकता है।

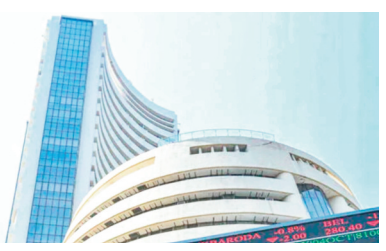

इस विधेयक को पेश करने की तैयारी में जुटे सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि इससे अमेरिका को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों पर सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करने का दबाव बनाने के लिए 'जबर्दस्त ताकत' मिलेगी। अमेरिकी प्रशासन पिछले साल अगस्त में ही भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क को बड़ाकर 50 प्रतिशत कर चुका है। इसमें से 25 प्रतिशत शुल्क रूसी तेल खरीद जारी रखने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया था। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ₹अमेरिकी शुल्क को लेकर नई चिंताओं और एफआईआई की लगातार बिकवाली के चलते घरेलू बाजारों में सतर्कता का माहौल बना रहा, जिससे मुनाफे की उम्मीदें फीकी पड़ गईं।

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक बढ़त में रहा, जबकि जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में बंद हुए। यूरोपीय बाजार हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बुधवार को ज्यादातर कमजोर रहे। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.75 प्रतिशत बढ़कर 60.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। बुधवार को सेंसेक्स 102.20 अंक गिरकर 84,961.14 और निफ्टी 37.95 अंक फिसलकर 26,140.75 पर बंद हुआ था।

अधिकतर भारतीय पेशेवरों की 2026 में नौकरी बदलने की योजनाः लिंक्डइन

नई दिल्ली। भारत में अधिकतर पेशेवर 2026 में एक नई भूमिका की तलाश में है। हालांकि अनिश्चितता एवं कौशल अंतराल के कारण कुछ लोग बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नई भूमिका के लिए एआई-संचालित भर्ती प्रक्रिया में खुद को उपयुक्त महसूस नहीं करते हैं। पेशेवर मंच लिंक्डइन के नए सर्वेक्षण के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में कृत्रिम मेधा (एआई) के बढ़ते उपयोग, आज की नौकरियों के लिए तेजी से बदलती कौशल आवश्यकताओं और तेजी से प्रतिस्पर्धी लेकिन चयनात्मक नौकरी बाजार के बीच 84 प्रतिशत पेशेवर नई नौकरी खोजने के लिए खुद को तैयार महसूस नहीं करते हैं।

लिंक्डइन के आंकड़ों के अनुसार, भारत में रिक्त पदों के लिए आवेदकों की संख्या 2022 की शुरुआत से दोगुनी से अधिक हो गई है जिससे प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई है। कई लोग खुद को इसके लिए तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, करीब 74 प्रतिशत ने कहा कि पिछले एक साल में योग्य प्रतिभाओं को ढूंढना और भी कठिन हो गया है।

लिंक्डइन की 'करियर एक्सपर्ट' एवं लिंक्डइन इंडिया की वरिष्ठ प्रबंध संपादक (न्यूज) निराजिता बनर्जी ने कहा कि भारत के रोजगार बाजार में करियर बनाने और प्रतिभा मूल्यांकन में एआई एक मूलभूत भूमिका निभाता है। पेशेवरों को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की स्पष्ट समझ की है कि उनके कौशल अवसरों में कैसे तब्दील होते हैं और भर्ती संबंधी निर्णय वास्तव में कैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि एआई उपकरण का उद्देश्यपूर्ण उपयोग किए जाने पर ये, लोगों को उनकी उपयुक्त भूमिकाओं की पहचान करने, उद्देश्यपूर्ण तैयारी करने और अपने सीखने को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने में मदद करके इस अंतर को पाट सकते हैं।

एकता कपूर के शो में लीड रोल अदा करेगी ऐश्वर्या शर्मा

मुंबई। काफी समय से चर्चाएं थीं कि टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट अलग-अलग रह रहे हैं और कपल जल्द ही तलाक ले सकता है। अब ऐश्वर्या शर्मा के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पर एक अच्छी खबर है। एक्ट्रेस जल्द ही एकता कपूर के शो में लीड रोल अदा करते दिख सकती हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक नई वेब सीरीज की तैयारी में जुटी हुई हैं। चर्चा है कि इस अपकमिंग प्रोजेक्ट में ऐश्वर्या शर्मा को मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किए जाने की संभावना है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो उनके अपोजिट टीवी एक्टर वरुण विजय नजर आ सकते हैं, जो इससे पहले 'ससुराल सिमर का' और 'अनुपमा' जैसे लोकप्रिय शोज का हिस्सा रह चुके हैं। इंडस्ट्री के एक सोर्स ने बताया कि मेकर्स ऐश्वर्या शर्मा से सीरियल को लेकर बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या शर्मा उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिनसे शो के लिए बातचीत हो रही है। बताया जा रहा है कि मेकर्स उन्हें लीड रोल में लेने को लेकर काफी सकारात्मक हैं। हालांकि, फिलहाल शो के टाइटल, स्टारकास्ट और रिलीज से जुड़ी किसी भी जानकारी पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। सूत्रों का कहना है कि ऐश्वर्या का किरदार भावनात्मक रूप से काफी मजबूत और गहराई लिए होगा। इस रोल को खास तौर पर ऐसे लिखा जा रहा है, जिससे बड़ी उम्र के दर्शकों के साथ-साथ डिजिटल ऑडियंस भी खुद को जोड़ सके। यह सीरीज लंबे स्टोरी फॉर्मेट में बनाई जाएगी, जैसा कि हाल के दिनों में बालाजी टेलीफिल्म्स की डिजिटल पेशकशों में देखने को मिला है। अब अगर एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें तो ऐश्वर्या शर्मा ने साल 2021 में शादी की थी, लेकिन अब करीब चार साल बाद दोनों अलग हो गए हैं।

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन फिर दिखेंगे साथ, 'भूत बंगला' 15 मई को होगी रिलीज

इस साल की सबसे चर्चित हॉरर-कॉमेडी फिल्मों में शुमार 'भूत बंगला' को लेकर दर्शकों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। यह फिल्म 14 साल बाद हॉरर-कॉमेडी के मास्टर डायरेक्टर प्रियदर्शन और सुपरस्टार अक्षय कुमार की जबरदस्त जोड़ी को एक बार फिर साथ लाती है। पहले पोस्टर और फिर मोशन पोस्टर के रिलीज़ होते ही फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर पहुंच गया था। अब मेकर्स ने इसकी रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया है, जिसने फैंस की बेसब्री और बढ़ा दी है। निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 'भूत बंगला' 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। हॉरर और कॉमेडी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ प्रियदर्शन-अक्षय कुमार की यह री-यूनियन दर्शकों को वही क्लासिक एंटरटेनमेंट देने का वादा करती है, जिसकी कमी बड़े पर्दे पर लंबे समय से महसूस की जा रही थी। रिलीज डेट की जानकारी साझा करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर पोस्ट किया और कैप्शन लिखा, ₹बंगले से एक खबर आई है! 15 मई 2026 को खुलेगा दरवाज़ा सिनेमाघरों में मिलते हैं 'भूत बंगला' ।फिल्म की एक और बड़ी ताकत इसकी दमदार स्टारकास्ट है। अक्षय कुमार के साथ इसमें तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता, असरानी और वामिका गब्बी जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के कुछ अहम हिस्सों की शूटिंग राजस्थान, जयपुर और हैदराबाद में की गई है, जो इसे भव्य विज़ुअल टच देती है। प्रियदर्शन की फिल्मों में इस तरह की पावरहाउस कास्ट का साथ आना अपने आप में एक बड़े सिनेमाई धमाके का संकेत देता है।

आज के दौर में भी टेलीविज़न प्रभावशाली और सशक्त माध्यम है : अपरा मेहता

मुंबई। जानी मानी चरित्र अभिनेत्री अपरा मेहता का कहना है कि आज के दौर में भी टेलीविजन प्रभावशाली और सशक्त माध्यम बना हुआ है। अपरा मेहता इन दिनों सन नियो के शो 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरीः बींदणी' में काम कर रही है। वह इस शो में राजश्री की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज के दौर में भी टेलीविजन प्रभावशाली और सशक्त माध्यम बना हुआ है। अपरा मेहता ने कहा कि मैंने खुद टेलीविजन को इन सालों में बदलते हुए देखा है और मुझे गर्व है कि मैं इस सफर का हिस्सा रही हूँ। जो भी शो अच्छा और सकारात्मक संदेश देता है, वह हमेशा दर्शकों को अपनी कहानी से जोड़ता है। टीवी पहले जैसा जरूर नहीं रहा, लेकिन यह खत्म होने वाला नहीं है। टीवी की पहुँच बहुत व्यापक है और इसके दर्शक आज भी बड़ी संख्या में हैं। यही वजह है कि टीवी आज भी बदलाव लाने और सही संदेश लोगों तक पहुँचाने का एक मजबूत माध्यम बना हुआ है। अपरा मेहता ने कहा कि मैं अपने ड्रामा के लिए दुनिया भर की सैर करती हूँ और मैंने देखा है कि विदेशों में रहने वाले लोग भारतीय टीवी से आज भी कितनी गहराई से जुड़े हैं। हो सकता है कि वे फिल्में नियमित रूप से न देखते हों, लेकिन टीवी जरूर देखते हैं। इसलिए हमारे लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम आज की सच्चाई को अपनी कहानी के जरिए दिखाएँ, न कि पुरानी सोच को। जैसा कि सन नियो के मेरे मौजूदा शो 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरीः बींदणी' में मेरा किरदार मानता है कि लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन, कहानी और मुख्य किरदारों के जरिए शो यह मजबूत संदेश देता है कि लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी है। आज भी कई जगहों पर लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, ऐसे में यह संदेश लोगों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरीः बींदणी' शो राजस्थान की एक गाँव की लड़की घेवर की कहानी है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसके परिवार में एक नवजात बच्चा आता है, जो दो अलग-अलग जिंदगियों को एक साथ जोड़ता है। प्यार, त्याग और छिपे हुए सच के बीच घेवर अपने हौसले और हिम्मत से अपनी सबसे कीमती चीज की रक्षा करती है। 'प्रथाओं की ओढ़े चुनरीः बींदणी' शो हर रोज रात नौ बजे, सिर्फ सन नियो पर प्रसारित होता है।

ट्रम्प ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए अमेरिका को 66 वैश्विक निकायों से अलग किया

संयुक्त राष्ट्र/वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों और भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) समेत 66 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का फैसला किया है।

ट्रंप ने इन संस्थाओं को 'अनावश्यक' और अमेरिका के हितों के "विरुद्ध" बताया। ट्रंप ने बुधवार को 'संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के प्रतिकूल अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका को बाहर निकालना' शीर्षक वाले एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भागीदारी करना या किसी भी रूप में उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के विपरीत है। व्हाइट हाउस द्वारा बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार, इनमें 31 संयुक्त राष्ट्र निकाय और 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं, जो 'अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि या संप्रभुता के विरुद्ध कार्य करते हैं।' ट्रंप ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे इन संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाले जाने संबंधी फैसले को 'यथाशीघ्र' लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र निकायों के मामले में, कानून द्वारा अनुमेय सीमा तक, इन संस्थाओं में भागीदारी या वित्तपोषण समाप्त करना ही वापसी माना जाएगा। जिन संगठनों से अमेरिका अलग हो रहा है, उनमें जलवायु परिवर्तन पर भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) भी शामिल है।

वर्तमान में आईएसए के 100 से अधिक देश हस्ताक्षरकर्ता हैं और 90 से अधिक देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए इसकी पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा जिन संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी पूरी सूची उन्हें प्राप्त हो गई है और इस पर बृहस्पतिवार को टिप्पणी की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने 'एक्स' पर कहा कि अमेरिका अब उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को न तो वित्तपोषित करेगा और न ही उनमें भागीदारी करेगा, जो अमेरिकी हितों को पूरा नहीं करते या कई मामलों में उनके विरुद्ध हैं।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने इन 66 संस्थानों को 'अपने दायरे में अनावश्यक, कुप्रबंधित, अपव्ययी, खराब ढंग से संचालित, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले तत्वों के कब्जे में या देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और समग्र समृद्धि के लिए खतरा' पाया है।

रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि अमेरिकी जनता के खून-पसीने और धन को ऐसे संस्थानों पर खर्च करना अब स्वीकार्य नहीं है, जिनसे बहुत कम या कुछ भी हासिल नहीं होता। करदाताओं के अरबों डॉलर विदेशी हितों पर खर्च करने के दिन अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों से अमेरिका को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी सूची यह दर्शाती है कि शांति और सहयोग के लिए बना व्यावहारिक अंतरराष्ट्रीय ढांचा अब 'वैश्विक शासन की एक विशाल संरचना' में बदल गया है, जो अक्सर प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों से कटा हुआ है। रुबियो ने कहा कि हम उन संस्थाओं में संसाधन, कूटनीतिक पूंजी और अपनी भागीदारी जारी नहीं रखेंगे, जो हमारे हितों से अप्रासंगिक या उनके विरोध में हैं। जहां सहयोग हमारे लोगों के हित में होगा, हम वहां सहयोग करेंगे और जहां नहीं होगा, वहां दृढ़ रहेंगे। रुबियो ने कहा कि आज राष्ट्रपति ट्रंप ने 66 अमेरिका-विरोधी, बेकार या अपव्ययी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा की। अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की समीक्षा अभी जारी है। जिन 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र निकायों से अमेरिका बाहर निकल रहा है, उनमें अंतरसरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यूक्रेन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग शामिल हैं।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के तहत अफ्रीका, लातिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र, एशिया-प्रशांत तथा पश्चिम एशिया के आर्थिक आयोग, शांति निर्माण आयोग और कोष, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भी सूची में शामिल हैं। ट्रंप संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियों के तीखे आलोचक रहे हैं। पिछले वर्ष 20 जनवरी को शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को फिर से बाहर निकालने का कार्यकारी आदेश जारी किया था, जो उनके पहले कार्यकाल के फैसले की पुनरावृत्ति थी।

अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती हफ्तों में ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की भागीदारी समाप्त करने, यूनेस्को की सदस्यता की समीक्षा करने और फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) को दी जाने वाली मदद रोकने का आदेश दिया था। पिछले वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान, राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? इसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह उन पर खरा नहीं उतर पा रहा है। अधिकतर मामलों में, कम से कम अभी, यह केवल कड़े शब्दों वाला पत्र लिखता है और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। खोखले शब्द युद्ध का समाधान नहीं करते।

क्वात्रा ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन से मुलाकात की

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने 'कैपिटल हिल' (संसद भवन परिसर) में स्पीकर माइक जॉनसन से मुलाकात की और पहलगाम हमले के बाद भारत के आतंकवाद रोधी प्रयासों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

जॉनसन से मुलाकात के बाद क्वात्रा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि आज 'कैपिटल हिल' में स्पीकर माइक जॉनसन से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के वास्ते उनके समर्थन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। क्वात्रा ने कहा कि उन्होंने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के आतंकवाद रोधी प्रयासों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जॉनसन को धन्यवाद दिया। भारतीय राजदूत ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी को रक्षा एवं सुरक्षा, तेल एवं गैस व्यापार, एआई (कृत्रिम मेधा) सहित प्रौद्योगिकी में साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते की दिशा में काम करने के दोनों देशों के प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

क्वात्रा 'क्वांटम कंप्यूटिंग' में हो रहे अत्याधुनिक शोध कार्यों को देखने के लिए न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर स्थित 'आईबीएम थॉमस जे. वाटसन रिसर्च सेंटर थिंक लैब' भी गए थे। उन्होंने कहा कि भारत में आईबीएम के विस्तार और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर चर्चा हुई, इस मिशन के तहत भारत विश्वस्तरीय अनुसंधान सहयोग और समर्पित नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है।

नेपालः पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की नीति को मंजूरी

काठमांडू। 'पेट्रोल में इथानोल मिलाने' की प्रक्रिया को अब नेपाल सरकार ने अंततः आगे बढ़ा दिया है। लगभग दो दशक से नीतिगत चर्चा के बावजूद इस पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। मंत्रिपरिषद की बुधवार को हुई बैठक ने 'पेट्रोल में इथानोल मिश्रण संबंधी आदेश-2082' को स्वीकृति देकर व्यावहारिक रूप से लागू करने का रास्ता खोल दिया है।

नेपाल ऑयल निगम के कार्यकारी निदेशक डॉ. चण्डिकाप्रसाद भट्ट के अनुसार, यह मंजूरी दो दशख स अटकी हुई थी। अब राजपत्र में प्रकाशित होने वाले आदेश जारी किए जाने से इसके कार्यान्वयन के लिए मजबूत आधार तैयार हो गया है। निगम का निष्कर्ष है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और स्वदेशी उद्योग को बहुआयामी लाभ होगा। कार्यकारी निदेशक भट्ट ने इथेनॉल को 'बायो फ्यूल' और पेट्रोल को 'मिनरल फ्यूल' बताते हुए कहा कि इनके मिश्रण से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण और नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वर्ष 2045 तक 'नेट-जीरो कार्बन' हासिल करने की प्रतिबद्धता के संदर्भ में इस योजना को अत्यंत सहायक बताया गया है।

जयशंकर ने पेरिस में जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड से इंडो-पैसिफिक की चुनौतियों पर चर्चा की

पेरिस (फ्रांस)। फ्रांस के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पहली बार अपने वाइमर (जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड) के समकक्षों के साथ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने इस दौरान अपने समकक्षों से भारत-यूरोपियन यूनियन संबंधों को मजबूत करने के अलावा इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) की चुनौतियों पर चर्चा की।

डॉ. जयशंकर ने एक्स पोस्ट पर फोटो के साथ यह जानकारी दी। उन्होंने कहा इस दौरान यूक्रेन संघर्ष पर विचारों को साझा किया गया। भारत ने खुली और स्पष्ट चर्चा में इन मुद्दों पर अपने विचार रखे। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन दुनिया को वाइमर और भारत के रुख से अवगत कराया गया। भारतीय विदेशमंत्री डॉ. जयशंकर ने इससे पहले फ्रांस के विदेशमंत्री जीन नोएल बैरट से मिलने के बाद कहा कि यूरोप वैश्विक स्तर पर अहम खिलाड़ी है और जरूरी है कि भारत और यूरोप के रिश्ते मजबूत हों। भारत और फ्रांस वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं। जयशंकर ने बताया कि भारत अगले कुछ हफ्तों में, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं की मेजबानी करेगा।

उल्लेखनीय है कि इंडो-पैसिफिक उभरता हुआ भू-राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। इसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के देश और जलक्षेत्र शामिल हैं। यह पूर्वी अफ्रीका तट से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला है और विश्व की अधिकांश आबादी और अर्थव्यवस्था का केंद्र है। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र व्यापार, सुरक्षा और समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन और समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत इसे 'मुक्त, खुला और समावेशी' क्षेत्र मानता है। आईपीओआई (इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव) भारतीय पहल है। इसका लक्ष्य समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है। अमेरिका की भी इस पर दिलचस्पी है। उसने आईपीईएफ (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) की पहल की है। एक तरह से यह आर्थिक सहयोग ढांचा है।